राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, रविवार , 15 मार्च 2026

वर्ष 14,अंक 322, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

जेल से रिहा युवक लापता, परिजनों ने एसपी से लगाई गुहार...03

विजयराघवगढ़ विस के बरही में 'कृषि महोत्सव' की भव्य तैयारी...12

रिश्वतखोरी मामले में गुरुग्राम के पूर्व DFSC अनिल कुमार को राहत, पंजाब एवं हरियाणा H C से मिली जमानत

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बादशाहपुर (गुरुग्राम)। खाद्य आपूर्ति विभाग में कथित रिश्वतखोरी और डिपो होल्डरों से कमीशन वसूली के चर्चित मामले में पूर्व जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) अनिल कुमार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। इससे पहले अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. गगन गीत कौर की अदालत उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी थी। अदालत में अनिल कुमार की पैरवी अधिवक्ता सतपाल यादव कर रहे हैं।

फरवरी में खारिज की थी याचिका

फरवरी में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अनिल कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उस समय शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता राहुल टुटेजा ने अदालत में दलील दी थी कि मामले में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद हैं और आरोप बेहद गंभीर हैं। इस बीच एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने मामले की जांच पूरी कर पूर्व डीएफएससी अनिल कुमार, सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी (एएफएसओ) विजय टांक और विभाग के अधिकारी प्रेम पूर्ण सिंह के विरुद्ध अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत ने आरोपितों को चालान की प्रति उपलब्ध कराई थी और मामले में आरोप तय करने के लिए सुनवाई की तारीख तय की थी।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में अनिल कुमार की ओर से अधिवक्ता सतपाल यादव पेश हुए थे। अदालत में यह भी बताया गया था कि एसीबी की जांच पूरी हो चुकी है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।

यह है पूरा मामला

मदनपुरी निवासी राशन डिपो होल्डर रूपेश अरोड़ा ने एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत दी थी कि खाद्य आपूर्ति विभाग के कुछ अधिकारी डिपो होल्डरों से कमीशन की अवैध वसूली करते हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि एएफएसओ विजय टांक, निरीक्षक प्रेम पूर्ण सिंह और डीएफएससी अनिल कुमार मिलकर राशन डिपो संचालकों से करीब 10 प्रतिशत तक कमीशन की मांग करते थे। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि मार्च 2024 में अनिल कुमार ने दबाव बनाकर शिकायतकर्ता से एक आईफोन 15 प्रो और एप्पल वाच रिश्वत के रूप में ली। वहीं एएफएसओ विजय टांक पर 35 हजार रुपये अपने बैंक खाते में लेने और निरीक्षक प्रेम पूर्ण सिंह पर 56 हजार रुपये का एसी लेने का आरोप लगाया गया था।

ट्रायल कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई

प्रारंभिक जांच के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए।

इसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने 11 जुलाई 2024 को तीनों अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 7, 7ए और 13 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान नवंबर 2025 में अनिल कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। बाद में उन्होंने अदालत में जमानत याचिका दायर की। जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिलने के बाद मामले में आगे की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में जारी रहेगी।

प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाने पर निगम की कार्रवाई, गुरुग्राम में दो कमर्शियल यूनिट्स सील

गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम की टीम ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए शहर की दो व्यावसायिक इकाइयों को सील कर दिया। इन इकाइयों पर लाखों रुपये का संपत्ति कर बकाया था, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, कर बकाया होने के बावजूद संबंधित संस्थानों द्वारा बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद निगम के जोन -चार क्षेत्र की टीम ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए दोनों संपत्तियों को सील कर दिया।

पहली कार्रवाई एमएस टेकप्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड पर की गई। यह संपत्ति जीएफ-202 एवं 204, जेएमडी पैसिफिक स्क्वायर, सेक्टर-16, गुरुग्राम में स्थित है। इस इकाई पर 34,61,639 रुपये का संपत्ति कर बकाया है, जिसके चलते निगम की टीम ने इसे सील कर दिया। दूसरी कार्रवाई पीबीजे एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड पर की गई, जो एलजी-14, स्टार माल, सेक्टर-30, गुरुग्राम में स्थित है। इस इकाई पर 35,48,307 रुपये का संपत्ति कर बकाया है। निगम द्वारा बकाया राशि जमा न करने के कारण इस संपत्ति को भी सील कर दिया गया। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि शहर में बकाया संपत्ति कर की वसूली के लिए आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। निगम ने सभी संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे समय पर अपना कर जमा करें, ताकि उन्हें इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई का सामना न करना पड़े।

बंगाल से महाजंगलराज का होगा खात्मा, बदलाव दीवारों पर लिखा जा चुका... कोलकाता में पीएम मोदी की हुंकार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पीएम मोदी ने कोलकाता में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज कोलकाता की धरती से पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है. सड़क, रेलवे और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है. इस दौरान पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार पर हमला भी बोला. उन्होंने कहा कि बंगाल में बदलाव अब दीवारों पर भी लिखा जा चुका है और लोगों के दिलों में भी छप चुका है. अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा. अब बंगाल से महाजंगलराज का खात्मा होगा।

पीएम ने कहा, ये प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत को नई रफ्तार देंगे, इनसे व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, लाखों लोगों का जीवन आसान होगा, उन्हें नए अवसर मिलेंगे.आज देश में रेलवे को आधुनिक बनाने का तेज अभियान चल रहा है.हमारा ये संकल्प है कि पश्चिम बंगाल इस अभियान में पीछे न रहे.इसीलिए केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी तेजी से विस्तार कर रही है

'बंगाल में महाजंगलराज खत्म होगा'

इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ममता सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि बंगाल में महाजंगलराज खत्म होगा, बदलाव अब दीवारों पर लिख चुका है. उन्होंने कहा कि निर्मन सरकार कुर्सी जाते देख बोखला गई है. उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार परिवर्तन को रोक नहीं पाएगी।

'एक बार फिर से बंगाल में कानून का राज होगा'

पीएम मोदी ने कहा कि एक बार फिर से बंगाल में कानून का राज होगा. उन्होंने कहा कि टीएमसी के किसी भी अत्याचारी को छोड़ा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि निर्मम सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है. उन्होंने कहा कि बंगाल से जंगलराज खत्म होकर ही रहेगा. उन्होंने कहा कि नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज चुका है।

'बंगाल के विकास में बीजेपी दिन रात लगी है'

उन्होंने कहा कि बंगाल के विकास में बीजेपी दिन रात लगी है. उन्होंने कहा की निर्मम सरकार रैली में जनसैलाब को रोक नहीं पाई. उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब बंगाल में कानून का राज लौटेगा. उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, और टीएमसी के अत्याचारों को भी नहीं बख्शा जाएगा. उन्होंने कहा कि यह निर्दयी सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, बदलाव की इस आंधी को रोक नहीं पाएगी।

'निर्मम सरकार जनसैलाब को रोक नहीं पाई'

पीएम मोदी ने कहा कि आज भी इस सभा को रोकने के लिए निर्मम सरकार ने सारे हथियार निकाल लिए. आप लोगों को आने से रोकने के लिए ब्रिज बंद करवा दिए, गाड़ियां रुकवा दी, ट्रैफिक जाम करवाया, भाजपा के झंडे उखड़वा दिए, पोस्टर फड़वा दिए. लेकिन निर्मम सरकार साफ-साफ देख लो, आज के जनसैलाब को रोक नहीं पाई हो. पीएम ने कहा किकल TMC ने इस रैली में आने वाले आप सभी लोगों को चोर कहकर गाली दी है. असली चोर कौन है, ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है उन्होंने कहा कि अपनी कुर्सी जाते हुए देखकर यहां की निर्मम सरकार बौखला गई है।

देश में गरमाया गैस संकट... संसद में भी सांसदों को नहीं मिल रही चाय- कांग्रेस M P

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मध्य पूर्व में बिगड़ हालातों की वजह से देश में गैस संकट पैदा हो गया है. जिसकी वजह से कई फूड रेस्टोरेंट के बंद पड़े हैं, गैस एजेंसियों के बाहर कतारों की खबरें हैं. इसके अलावा देश के कई हिस्सों में लोगों ने इसको लेकर प्रदर्शन भी किया है. गैस संकट की आंच संसद तक भी पहुंच गई है. शनिवार को LPG संकट को लेकर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई।

सरकार का दावा है कि स्थिति काबू में है और वह डिमांड को पूरा करने के लिए काम कर रही है. लेकिन कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच के भारी अंतर को उजागर किया. कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सांसदों को संसद में चाय मिलने में भी दिक्कत हो रही है और उन्होंने कहा कि लोगों 'कालाबाजारी' के चलते बढ़ी हुई कीमतों लिए 1500 से 2000 रुपये देने पड़ रहे हैं।

क्या बोले कांग्रेस नेता?

कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने कहा, 'इसमें कोई शक नहीं है कि कमी है. मैं रोज़ा (व्रत) रख रहा हूं, लेकिन कल संसद में चर्चा का विषय यह था कि जब सांसदों ने संसद कैंटीन में चाय या कॉफ़ी मांगी, तो उन्हें बताया गया कि यह उपलब्ध नहीं है. और फिर भी, आप दावा करते हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं, जिसमें कीमतें 1500 से 2000 रुपये तक मांगी जा रही हैं. जावेद खान ने सरकार पर कई आयोर लगाए. उन्होंने कहा कि सरकार भले ही कहे कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है. उन्होंने दावा किया कि संसद में ही सांसदों को चाय-कॉफी नहीं मिली, क्योंकि कैंटीन में गैस खत्म हो गई थी. उन्होंने ये भी कहा कि वह खुद रोजा रख रहे हैं, लेकिन संसद में इस मुद्दे पर चर्चा जरूरी थी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पलटवार

उन्होंने विपक्ष पर जिम्मेदारी न निभाने का आरोप लगाया. निर्मला ने कहा कि पश्चिम एशिया के हालात के कारण सप्लाई चेन में जो चुनौतियां आ रही हैं, उनसे निपटने के लिए सरकार ने 50,000 करोड़ रुपये का फंड बनाया है, लेकिन विपक्ष इसे सुनने को तैयार नहीं है.

जबलपुरः मां ने खाना देने में की देरी... बेटे ने धारदार हथियार से कर दी हत्या

एमपी के जबलपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां खाना परोसने में देरी होने से नाराज बेटे ने अपनी ही मां की धारदार हथियार से हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी रातभर मां के शव के पास ही बैठा रहा. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. घटना जिले के कुंडम थाना क्षेत्र के जमुनिया बदरिया गांव की है. पुलिस के अनुसार गांव निवासी श्याम सिंह मरावी अपनी 50 वर्षीय पत्नी जमुना बाई मरावी, बेटे दीपक मरावी, बसोरी और बेटी प्रीति के साथ रहते हैं. बताया जा रहा है कि बसोरी और प्रीति मानसिक रूप से बीमार हैं. बुधवार सुबह श्याम सिंह रोज की तरह मजदूरी के लिए घर से निकल गया था. रात में जब वह गांव लौटा तो अपने मित्र के घर खाना खाकर वहीं सो गया. इसी बीच घर पर दीपक और उसकी मां जमुना बाई के बीच खाना देने को लेकर कहासुनी हो गई।

तसले और हंसिया से हमला की हत्या

गुस्से में आकर दीपक ने पहले घर में रखा तसला और फिर धारदार हथियार हंसिया उठाकर मां पर हमला कर दिया. हमले में जमुना बाई के चेहरे पर गंभीर चोटें आईं और अत्यधिक खून बहने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

शव को साड़ी से ढंककर रातभर बैठा रहा आरोपी बेटा

वारदात के बाद आरोपी बेटे ने मां के शव को साड़ी से ढंक दिया और रातभर एमपी के जबलपुर जिले से एक दिल उसी के पास बैठा रहा. उस समय घर में मौजूद उसका मानसिक रूप से बीमार भाई बसोरी और बहन प्रीति को इस घटना की जानकारी तक नहीं थी।

संक्षिप्त ख़बरें

भारत विश्वगुरु बनने का मौका चूक गया...गैस की किल्लत पर अखिलेश ने सरकार को घेरा

इजराइल अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग की वजह से भारत में गैस की किल्लत हो रही है. LPG सिलेंडर लेने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं. इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान सामने आया है. उन्होंने मुंबई में गैस संकट और अंतरराष्ट्रीय युद्ध की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है।

मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मौजूदा युद्ध संकट के दौरान भारत के पास दुनिया को शांति का संदेश देने और विश्वगुरु बनने का बड़ा अवसर था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की. उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास हमेशा युद्ध के खिलाफ और शांति के पक्ष में रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस भूमिका निभाने में नाकाम रही।

'तो आज भारत को विश्वगुरु कहा जाता...'

सपा प्रमुख ने कहा कि अगर भारत इस संघर्ष की खुले तौर पर निंदा करता और दुनिया को शांति का संदेश देता तो आज भारत को विश्वगुरु कहा जाता. उन्होंने कहा कि Strait of Hormuz से भारत की ओर कितने जहाज आ रहे हैं, इसकी वास्तविक जानकारी किसी के पास नहीं है. उन्होंने कहा कि कोई कह रहा है कि एक जहाज आ रहा है, तो कोई दो जहाज आने की बात कर रहा है, लेकिन असली स्थिति क्या है यह स्पष्ट नहीं है।

'सबसे ज्यादा अफवाहें बीजेपी के लोग ही फैलाते हैं'

अखिलेश ने आरोप लगाया कि युद्ध संकट के कारण देश में एलपीजी गैस सिलेंडरों की कमी हो गई है और आम लोगों को गैस नहीं मिल पा रही है. इसके बावजूद सरकार इस समस्या को हल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है. बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर दूसरों पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हैं, जबकि असल में सबसे ज्यादा अफवाहें बीजेपी के लोग ही फैलाते हैं।

'बीजेपी नफरत की राजनीति करती है'

वहीं संभल मस्जिद मुद्दे पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भारत में हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किया गया है, लेकिन बीजेपी नफरत की राजनीति करती है और समाज को बांटने का काम करती है. उन्होंने कहा कि हर धर्म हमें शांति का संदेश देता है।

अंबेडकर को सम्मान दिया नहीं, कांशीराम को क्या देगी... कांग्रेस के प्रस्ताव पर मायावती का निशाना

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के अनुयायियों और समर्थकों को कांग्रेस के खिलाफ सतर्क रहने की सलाह दी है. साथ ही कहा है कि कांग्रेस की दलित-विरोधी सोच और मानसिकता के कारण ही BSP का गठन करना पड़ा था. मायावती ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर को कभी भी उचित सम्मान नहीं दिया और न ही कांशी राम के निधन पर एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित किया.

यह बात तब सामने आई जब शुक्रवार को लखनऊ में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बहुजन समाज पार्टी (BSP) के संस्थापक कांशीराम की जयंती के कार्यक्रम में हिस्सा लिया. मायावती ने X पर एक पोस्ट में कहा, 'जैसा कि सभी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में सत्ता में रहते हुए अपने कई सालों के शासनकाल में, दलितों के मसीहा और भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता परम पूजनीय बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर को कभी भी उचित सम्मान और आदर नहीं दिया. और न ही उन्हें 'भारत रत्न' की उपाधि से सम्मानित किया. तो फिर यह पार्टी अब सम्मानित श्री कांशी राम जी को इस उपाधि से कैसे सम्मानित कर सकती है? '

उन्होंने आगे कहा, 'यह वही कांग्रेस पार्टी थी, जिसने केंद्र में सत्ता में रहते हुए, इनके निधन पर एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था और न ही उस समय . U P .में सत्ता में रही SP सरकार ने कोई राजकीय शोक घोषित किया था. इसी तरह, दलित समुदाय द्वारा बनाए गए कई संगठन और पार्टियां, जो अब दूसरी पार्टियों के हाथों में चली गई हैं, वे हमेशा अपने फायदे के लिए उनके नाम का दुरुपयोग करने में लगी रहती हैं।

BSP को कमजोर करने वाला कदम- मायावती

मायावती ने कहा, 'अब ये सभी पार्टियां सम्मानित श्री कांशी राम जी द्वारा स्थापित BSP पार्टी को कमजोर करने के लिए लगातार हर तरह की रणनीतियां अपना रही हैं. इसलिए उनके अनुयायियों और समर्थकों को इनके प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए. उन्हें विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी से सतर्क रहना चाहिए, जिसकी दलित-विरोधी सोच और मानसिकता के कारण ही शुरू में BSP का गठन करना पड़ा था. 'उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से यह भी अपील की कि वे कांशी राम की जयंती के अवसर पर BSP द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें. साथ ही कल यानी 15 मार्च 2026 को आदरणीय श्री कांशीराम जी की जयंती के अवसर पर पार्टी सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने जिस पार्टी BSP की स्थापना की थी, उसके सभी कार्यक्रम पूरे देश में (U P सहित) सफल हों, यही मेरी अपील है. ' बता दें कि जयंती कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कांशीराम की विरासत का सम्मान किया और कहा, 'अगर जवाहरलाल नेहरू जीवित होते, तो कांशीराम कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री होते।

बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम

1984 में कांशी राम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की. जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यकों से मिलकर बने 'बहुजन समाज' को एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में एकजुट करना था. वे सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह अडिग रहे. उन्होंने बहुजन समुदायों के बीच समर्थन जुटाने के लिए अथक प्रयास किए और लाखों लोगों को समानता और न्याय के इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।

रिटायर महिला कर्मचारी से एरियर भुगतान के लिए ली रिश्वत... डिप्टी C M ब्रजेश पाठक ने लिया एक्शन; गिरी गाज

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बस्ती जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रमजोत में तैनात वरिष्ठ सहायक प्रदीप श्रीवास्तव निलंबित कर दिया गया है. रिटायर महिला कर्मचारी से एरियर भुगतान के बदले 45 हजार रुपये घूस लेने के आरोप में उन्हें निलंबित किया गया है. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तत्काल जांच के आदेश दिए. इसके बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया।

रिटायर महिला कर्मचारी ने अपने भाई के साथ मिलकर रिश्वत लेते हुए प्रदीप श्रीवास्तव का वीडिया बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

रिटायर एएनएम से मांगी थी रिश्वत

जानकारी के मुताबिक विक्रमजोत सीएचसी के तहत एएनएम सुनीता कार्यरत थीं. सेवानिवृत्ति के बाद उनके एरियर भुगतान की प्रक्रिया चल रही थी. आरोप है कि इस भुगतान के बदले वरिष्ठ सहायक प्रदीप श्रीवास्तव ने उनसे 45 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. पीड़िता सुनीता ने अपने भाई के साथ मिलकर प्रदीप श्रीवास्तव को रिश्वत देते समय वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

जांच के बाद हुई कार्रवाई

मामला सामने आने के बाद चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की निदेशक प्रशासन अलका वर्मा ने आरोपी को निलंबित कर दिया. निलंबन के बाद प्रदीप श्रीवास्तव को चित्रकूट धाम मंडल के अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय से संबद्ध किया गया है. विभाग ने आरोपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी है. मामले की जांच के लिए चित्रकूट धाम मंडल के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर निदेशक को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

कोर्ट के आदेश के बाद भी ली थी रिश्वत

जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला कर्मचारी सुनीता वर्मा का विभाग में काफी समय से एरियर बकाया था. जिसके बाद वह कोर्ट चली गई और कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए चार सप्ताह के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया था. आरोप है कि इसके बावजूद फाइल आगे बढ़ाने के लिए बाबू प्रदीप श्रीवास्तव ने रिश्वत ली।

ईरान-इजरायल युद्ध में भागलपुर के मरीन इंजीनियर की मौत, ऑयल टैंकर लेकर जा रहे थे सिंगापुर; मिसाइल हमले में गई जान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ईरान- इजरायल संघर्ष के बीच बिहार के भागलपुर जिले के एक मरीन इंजीनियर की दर्दनाक मौत हो गई. भागलपुर के कहलगांव प्रखंड के निवासी देवनंदन प्रसाद सिंह एक ऑयल टैंकर जहाज पर एडिशनल चीफ इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे. ड्यूटी के दौरान इराक के बसरा पोर्ट के पास उनके जहाज पर मिसाइल से हमला हुआ. सभी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद गए, जिसमें उनकी जान चली गई।

जानकारी के अनुसार, 11 मार्च 2026 की रात फारस की खाड़ी में इराक के बसरा तट के पास एक कच्चे तेल से भरे टैंकर 'सेफसी विष्णु' पर हमला हुआ. यह जहाज मार्शल आइलैंड्स के झंडे के तहत चल रहा था और बसरा से सिंगापुर की ओर जा रहा था. बताया जा रहा है कि हमले के दौरान जहाज में विस्फोट हुआ और उसमें आग लग गई. हमले के बाद जहाज पर मौजूद क्रू में अफरा-तफरी मच गई. जान बचाने के लिए कई क्रू मेंबर समुद्र में कूद गए।

27 क्रू मेंबर्स की बचा ली गई जान

इराकी बंदरगाह प्राधिकरण और रेस्क्यू टीम ने अभियान चलाकर अधिकांश लोगों को सुरक्षित निकाल लिया. करीब 27 से अधिक क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया, लेकिन देवनंदन प्रसाद सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई. देवनंदन प्रसाद सिंह मूल रूप से भागलपुर जिले के रानीबिमियां गांव (कहलगांव) के रहने वाले थे. परिवार के अनुसार घटना से कुछ समय पहले उन्होंने घर पर फोन कर बताया था कि वे समुद्र में ड्यूटी पर हैं और ज्यादा बात नहीं कर सकते।

पार्थिव शरीर को लेकर परिवार परेशान

कुछ घंटों बाद कंपनी से हमले और उनकी गंभीर हालत की सूचना मिली, जिसके बाद उनकी मौत की खबर आई. उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं. बेटा जापान में निजी कंपनी में काम करता है, जबकि बेटी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही है. परिवार का कहना है कि देवनंदन का पार्थिव शरीर अभी इराक में है. उनके भाई कृष्णानंदन और पत्नी कुमकुम दिल्ली पहुंचे हैं, ताकि भारत सरकार और संबंधित कंपनी से मदद मिल सके. लेकिन अब तक कोई ठोस सहायता नहीं मिली है।

परिवार ने क्रेंद सरकार लगाई मदद की गुहार

परिवार ने केंद्र सरकार से अपील की है कि मरीन इंजीनियर के पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ भागलपुर लाया जाए, ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके. मृतक देवनंदन की मां की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है. वहीं, परिजनों के मुताबिक दिल्ली में मौजूद उनकी पत्नी भी अब अस्पताल में भर्ती है. देवनंदन सिंह की भांजी रूबी देवी और भांजे अमन ने बताया कि हम लोगों की केवल एक ही मांग है कि उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान भागलपुर लाया जाए ताकि हम लोग कम से कम उनके आखिरी दर्शन कर सकें.

हमारे परिवार के लिए वह एक मजबूत स्तंभ थे. मौत की खबर के बाद कंपनी और सरकार कीओर से कोई मदद नहीं की जा रही है. हम लोग पलके बिछाए उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है. देवनंदन की पत्नी और उनके भाई दिल्ली उन्हें लाने के लिए गए हुए हैं, लेकिन वहां भी उनकी मदद नहीं की जा रही है. देवनंदन अपने काम के प्रति बहुत कर्मठ थे और 1993 से ही शिपिंग कंपनी के साथ जुड़े हुए थे. मुंबई में वह अपनी पत्नी के साथ रहते थे।

राष्ट्रवाद का बदलता स्वरूप, सत्ता बनाम सेवा और समर्पण

वर्तमान समय में राष्ट्रवाद अपने सबसे जटिल, विरोधाभासी और बहुअर्थी दौर से गुजर रहा है, यह वह राष्ट्रवाद नहीं रह गया है जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान त्याग, नैतिक साहस, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक समरसता का प्रतीक था, बल्कि यह एक ऐसा राष्ट्रवाद बनता जा रहा है जिसे बार-बार सत्ता की भाषा में परिभाषित किया जा रहा है, आज राष्ट्र सरकार का पर्याय बनने की ओर अग्रसर है और सरकार की आलोचना को राष्ट्रविरोध के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, यही वह बिंदु है जहाँ राष्ट्रवाद अपनी आत्मा खोने लगता है और लोकतंत्र अपने आधार, आज जब चुनावी सभाओं, टीवी स्टूडियो और सोशल मीडिया मंचों पर राष्ट्रवाद को धर्म, जाति, सैन्य शक्ति और भावनात्मक उन्माद के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है, तब यह प्रश्न अनिवार्य हो जाता है कि क्या राष्ट्र प्रेम का अर्थ केवल सत्ता के समर्थन तक सीमित रह गया है, हाल के वर्षों में यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि आतंकी घटनाओं, सीमा विवादों, सैन्य अभियानों और ऐतिहासिक स्मृतियों का चयनित उपयोग कर भावनात्मक ध्रुवीकरण को तेज किया गया है, असहमति को राष्ट्रद्रोह, प्रश्न को साजिश और आलोचना को देश के खिलाफ खड़े होने का प्रमाण बताया गया है, यह प्रवृत्ति केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि वैश्विक स्तर पर लोकतंत्रों के भीतर उभरते अति राष्ट्रवाद का साझा संकट है, अमेरिका में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अविश्वास, रूस में सत्ता केंद्रित राष्ट्रवाद, चीन में सर्वव्यापी राज्य और एशिया व अफ्रीका में सैन्य प्रभुत्व की राजनीति यह संकेत देती है कि राष्ट्रवाद अब नागरिकों को सशक्त करने के बजाय उन्हें नियंत्रित करने का माध्यम बनता जा रहा है, भारत जैसे विविधता से भरे समाज में यह परिवर्तन और भी खतरनाक है क्योंकि यहाँ राष्ट्र का अर्थ बहुलता, सहअस्तित्व और संवैधानिक संतुलन से जुड़ा रहा है, किंतु वर्तमान राजनीतिक विमर्श में बहुलता को कमजोरी और असहमति को बाधा के रूप में चित्रित किया जा रहा है, सत्ता की निरंतरता के लिए जातिगत समीकरणों का सूक्ष्म लेकिन आक्रामक उपयोग, धार्मिक पहचान का राजनीतिकरण और लोकलुभावन योजनाओं की होड़ लोकतंत्र को तात्कालिक लाभ की राजनीति में कैद कर रही है, मुफ्त उपहार, नकद हस्तांतरण और प्रतीकात्मक घोषणाएँ जनता को क्षणिक संतोष तो देती हैं लेकिन दीर्घकालिक आर्थिक अनुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्थागत सुधार जैसे मूल प्रश्नों को हाशिए पर धकेल देती हैं, लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति माना जाता है, किंतु आज सत्ता को स्थायित्व और राष्ट्रहित को सत्ता की निरंतरता से जोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है, इससे अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को वैधता मिलने लगती है, हाल के वर्षों में दलबदल की बढ़ती घटनाएँ, विचारधारा से अधिक सत्ता की प्राथमिकता और राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का क्षरण यह दर्शाता है कि राजनीति सिद्धांत से नहीं बल्कि अवसर से संचालित हो रही है, जातिवादी मतदान और पहचान आधारित ध्रुवीकरण के कारण खाप पंचायतों जैसी समानांतर सत्ता संरचनाएँ पुनः सामाजिक स्वीकृति पाने लगी हैं, जो संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी है, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के संवैधानिक आदर्शों के बावजूद धार्मिक आस्थाओं के नाम पर नीतिगत हस्तक्षेप और व्यक्तिगत जीवनशैली पर नियंत्रण यह प्रश्न उठाता है कि राष्ट्रवाद कहीं नागरिक स्वतंत्रताओं का शत्रु तो नहीं बनता जा रहा, पशु व्यापार, भोजन की पसंद और सांस्कृतिक व्यवहार जैसे विषय जब राज्य के नियंत्रण का विषय बनते हैं तब लोकतंत्र का स्वरूप धीरे-धीरे नैतिक निगरानी में बदलने लगता है, अति राष्ट्रवाद का सबसे खतरनाक पक्ष यह है कि वह भय पैदा करता है, भय बाहरी शत्रु का, भय आंतरिक दुश्मन का और भय असहमति का, और भय जब राजनीति का आधार बनता है तब लोकतंत्र केवल चुनावी औपचारिकता बनकर रह जाता है, इतिहास साक्षी है कि बीसवीं सदी में जर्मनी, इटली और स्पेन में इसी भय आधारित राष्ट्रवाद ने फासीवाद को जन्म दिया, एशिया में पाकिस्तान, म्यांमार और उत्तर कोरिया में सुरक्षा और राष्ट्ररक्षा के नाम पर सैन्य प्रभुत्व लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करता रहा है, भारत में भी यदि राष्ट्रवाद को केवल सैन्य शक्ति, बहुमत की भावना और नेता-केंद्रित आस्था से जोड़ा गया तो यह संविधान द्वारा प्रदत्त संतुलन को कमजोर करेगा, लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, संस्थाओं की स्वायत्तता और कानून के समक्ष समानता का नाम है, किंतु वर्तमान विमर्श में बहुमत को अंतिम सत्य और संख्या को नैतिक वैधता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, मीडिया के एक बड़े हिस्से द्वारा सत्ता समर्थक राष्ट्रवादी नैरेटिव का प्रसार, सोशल मीडिया पर ट्रोल संस्कृति और चयनित सूचना का उग्र प्रसार लोकतांत्रिक संवाद को संकीर्ण और आक्रामक बना रहा है, ऐसे समय में सिविल सोसाइटी, लेखक, पत्रकार, शिक्षाविद और न्यायिक संस्थाओं की भूमिका निर्णायक हो जाती है, यदि यह वर्ग चुप रहता है तो लोकतंत्र धीरे-धीरे आत्मसमर्पण कर देगा, राष्ट्रवाद का पुनर्पाठ आवश्यक है जहाँ राष्ट्र सरकार से बड़ा हो, संविधान सत्ता से ऊपर हो और नागरिक की गरिमा सर्वोपरि मानी जाए, राष्ट्र प्रेम का अर्थ प्रश्न करना, जवाबदेही माँगना और संस्थाओं को मजबूत करना भी होना चाहिए, न कि केवल नारे लगाना और भीड़ का हिस्सा बन जाना, तात्कालिक लोकप्रियता, भावनात्मक ध्रुवीकरण और सत्ता लोलुपता के स्थान पर दीर्घकालिक नीतिगत दूरदर्शिता, सामाजिक संतुलन और संवैधानिक नैतिकता को केंद्र में लाना ही लोकतंत्र को बचा सकता है, अन्यथा राष्ट्रवाद का यह बदला हुआ रूप राष्ट्र को जोड़ने के बजाय उसे भीतर से खोखला करता चला जाएगा और इतिहास एक बार फिर हमें चेतावनी देगा कि लोकतंत्र का पतन अचानक नहीं बल्कि तालियों, नारों और मौन के बीच धीरे-धीरे होता है।

संजीव ठाकुर

संपादकीय

हर खरीद में छुपा है आपका अधिकार - जानिए, समझिए, अपनाइए

[उपभोक्ता की जागरूकता ही बाजार की असली निगरानी]

[उपभोक्ता चेतना: भरोसेमंद और टिकाऊ बाजार की कुंजी]

बाजार की इस विशाल दुनिया में हम सब किसी न किसी रूप में उपभोक्ता हैं। हमारा पहनावा, हमारा भोजन और हमारी रोजमर्रा की सेवाएँ—ये सभी हमें उपभोक्ता की पहचान देती हैं। पर सवाल यह है कि क्या हर उपभोक्ता अपने अधिकारों से सचमुच परिचित है? क्या उसे यह पता है कि बाजार से उसे क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं? यदि नहीं, तो यह जागरूकता आखिर आएगी कब और कैसे? इन्हीं प्रश्नों को केंद्र में रखकर हर वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ताकि उपभोक्ता अपने अधिकारों को समझें, उनके लिए आवाज उठाएँ और एक निष्पक्ष व पारदर्शी बाजार व्यवस्था की मांग को मजबूत कर सकें।

तेजी से बदलते बाजार में उपभोक्ता की सुरक्षा और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण आधार बन गए हैं। इसी संदर्भ में वर्ष 2026 के लिए इस दिवस की थीम 'सुरक्षित उत्पाद, आश्वस्त उपभोक्ता' निर्धारित की गई है। यह केवल औपचारिक विषय नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं में सुरक्षा और भरोसा मजबूत करने का संदेश है। जब बाजार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूपों में तेजी से फैल रहा है, तब उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है। इसलिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षित, प्रमाणित और भरोसेमंद उत्पाद व सेवाएँ मिलना जरूरी है। साथ ही बाजार व्यवस्था भी ऐसी होनी चाहिए, जहाँ पारदर्शिता, गुणवत्ता और सुरक्षा के साथ विकल्प उपलब्ध हों, ताकि उपभोक्ता विश्वास के साथ खरीदारी कर सकें। केवल उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी देना ही पर्याप्त नहीं है। असली चुनौती यह है कि आज भी बड़ी संख्या में लोग अपने अधिकारों से अनजान हैं। उन्हें यह तक पता नहीं होता कि खराब गुणवत्ता का उत्पाद मिलने या किसी सेवा में धोखा होने पर शिकायत कहाँ और कैसे दर्ज कराई जाए। कई बार लोग शिकायत करने से इसलिए भी बचते हैं कि उन्हें लगता है, इससे कोई ठोस बदलाव नहीं होगा। यही उदासीन सोच और चुप्पी व्यापारिक अनियमितताओं को पनपने का अवसर देती है।

अक्सर बाजार में उपभोक्ता गलत जानकारी, भ्रामक विज्ञापनों, मिलावटी उत्पादों और अनुचित कीमतों का शिकार बनते हैं। डिजिटल युग ने इस चुनौती को और बढ़ा दिया है, जहाँ ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी और नकली उत्पादों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में उपभोक्ताओं का जागरूक होना और अपने अधिकारों की रक्षा करना पहले से अधिक जरूरी हो गया है। भारत में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया है, जो उन्हें सुरक्षा, सूचना, सुनवाई, शिकायत निवारण और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार देता है। लेकिन ये कानून तभी प्रभावी बनते हैं, जब उपभोक्ता स्वयं सतर्क और जागरूक हों।

वैश्विक स्तर पर भी अब उपभोक्ता अधिकारों को एक नई दिशा देने की पहल हो रही है। अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता संगठन और इसके सदस्य संगठन टिकाऊ जीवनशैली को बढ़ावा देने और उसे सरल व सुलभ बनाने के प्रयास कर रहे हैं। यदि उपभोक्ता अपनी खरीदारी की आदतों में बदलाव लाएँ, तो वे न केवल अपने स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे सकते हैं। प्लास्टिक के स्थान पर पुनः उपयोग योग्य वस्तुओं को अपनाना, जैविक खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देना और अनावश्यक उपभोग से बचना—ये सभी टिकाऊ जीवनशैली की ओर सकारात्मक कदम हैं।

हालाँकि यह परिवर्तन तभी संभव है, जब उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदारी निभाएँ। हर व्यक्ति को अपने क्रय-विक्रय के निर्णय सोच-समझकर लेने चाहिए। किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता की जाँच करना, प्रमाणित विक्रेताओं से ही खरीदारी करना और किसी धोखाधड़ी या अनुचित व्यवहार की स्थिति में उचित मंच पर शिकायत दर्ज कराना जरूरी है। जब उपभोक्ता सचेत और सक्रिय होंगे, तभी कंपनियाँ भी अधिक जवाबदेह बनेंगी और बाजार में अनुचित व्यापारिक प्रथाओं पर प्रभावी अंकुश लग सकेगा।

यह अवसर महज़ जागरूकता तक सीमित नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण संकल्प लेने का भी समय है। यह हमें याद दिलाता है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क रहें तथा हर खरीद-फरोख्त का निर्णय समझदारी, जिम्मेदारी और दूरदृष्टि के साथ लें। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को भली-भाँति समझेगा और टिकाऊ जीवनशैली को अपनाने की दिशा में सचेत कदम बढ़ाएगा, तब निश्चित रूप से एक ऐसी बाजार व्यवस्था का निर्माण संभव होगा जो न्यायसंगत, पारदर्शी और पर्यावरण-अनुकूल हो। उपभोक्ता अधिकारों की अवधारणा किसी एक दिन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह निरंतर चलने वाली एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है। यह केवल व्यक्तिगत सुरक्षा और सुविधा का प्रश्न नहीं, बल्कि पूरे समाज की भलाई, पारदर्शिता और संतुलित विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब उपभोक्ता अपने अधिकारों को सही मायनों में समझेंगे, अनुचित व्यापारिक प्रथाओं के विरुद्ध साहसपूर्वक आवाज उठाएँगे और जागरूक होकर टिकाऊ विकल्पों को अपनाएँगे, तभी वास्तव में एक संतुलित, न्यायपूर्ण और सशक्त उपभोक्ता संस्कृति का निर्माण संभव हो सकेगा।

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

ट्रम्प की टैरिफ राजनीति और भारत के खिलाफ आर्थिक दबाव की नई रणनीति

वैश्विक व्यापार की राजनीति अक्सर केवल आर्थिक हितों तक सीमित नहीं रहती बल्कि इसके पीछे भू-राजनीतिक रणनीतियां और शक्ति संतुलन की जटिल चालें भी छिपी होती हैं। हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत और चीन सहित 16 प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों के खिलाफ तथाकथित अनुचित व्यापार व्यवहार की जांच शुरू करना इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनके प्रशासन द्वारा अपनाई जा रही यह नीति केवल व्यापारिक नियमों का मामला नहीं है बल्कि वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धा में बढ़ते देशों को नियंत्रित करने का प्रयास भी मानी जा रही है।

पिछले महीने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया था। यह फैसला प्रशासन की व्यापारिक रणनीति के लिए बड़ा झटका माना गया। इसके बाद ट्रम्प प्रशासन ने नया कानूनी रास्ता खोजते हुए ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 301 के तहत जांच की प्रक्रिया शुरू की। इस प्रावधान के तहत अमेरिका को यह अधिकार मिलता है कि यदि किसी देश पर अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप साबित होता है तो वह उस देश के खिलाफ एकतरफा टैरिफ या अन्य व्यापारिक प्रतिबंध लगा सकता है।

अमेरिका का आरोप है कि कुछ देश अपनी घरेलू जरूरत से अधिक उत्पादन करते हैं और उस अतिरिक्त माल को सस्ते दामों पर वैश्विक बाजार में बेचते हैं। इसे डंपिंग कहा जाता है। साथ ही अमेरिका यह भी दावा करता है कि कई देश सरकारी सब्सिडी देकर अपने उत्पादों को कृत्रिम रूप से सस्ता बनाते हैं ताकि वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा में आगे रह सकें। अमेरिका का यह भी कहना है कि कुछ देश अपनी मुद्रा को कमजोर बनाए रखते हैं जिससे उनके निर्यात को बढ़ावा मिलता है और अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होता है।

हालांकि इस पूरे मामले को केवल आर्थिक तर्कों के आधार पर समझना पर्याप्त नहीं है। वैश्विक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम उस समय उठाया गया है जब भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं तेजी से वैश्विक व्यापार और उत्पादन के केंद्र बन रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विनिर्माण क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है और कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां चीन के विकल्प के रूप में भारत की ओर रुख कर रही हैं। ऐसे समय में अमेरिका द्वारा इस प्रकार की जांच शुरू करना कई विशेषज्ञों को रणनीतिक दबाव की नीति जैसा प्रतीत होता है।

ट्रम्प प्रशासन की यह नीति दरअसल अमेरिका फर्स्ट के उस सिद्धांत से जुड़ी है जिसे ट्रम्प ने अपने राजनीतिक अभियान का आधार बनाया था। उनका मानना रहा है कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था ने अमेरिकी उद्योगों और कामगारों को नुकसान पहुंचाया है। इसी सोच के तहत उन्होंने पहले भी कई देशों पर टैरिफ लगाए थे और व्यापारिक समझौतों को दोबारा बातचीत के लिए मजबूर किया था।

लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह नीति वैश्विक व्यापार के लिए अस्थिरता पैदा करती है। यदि अमेरिका अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ लगातार टैरिफ का इस्तेमाल करता है तो इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित होंगी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तनाव बढ़ेगा। इसका असर केवल संबंधित देशों पर ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

भारत के संदर्भ में यह मामला और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार ने वर्ष 2029 तक देश को वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। ऐसे समय में यदि बड़े बाजार भारत के निर्यात पर टैरिफ लगाने लगते हैं तो इससे भारतीय उद्योगों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। हालांकि यह भी सच है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में व्यापारिक कूटनीति को मजबूत किया है। भारत अब केवल एक उपभोक्ता बाजार नहीं बल्कि एक बड़ा उत्पादन केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं जैसी नीतियों ने वैश्विक कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित किया है। इसके अलावा भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते भी किए हैं जिससे उसके निर्यात के नए रास्ते खुल रहे हैं।

अमेरिका द्वारा शुरू की गई इस जांच में भारत के अलावा चीन यूरोपीय संघ जापान दक्षिण कोरिया मैक्सिको वियतनाम ताइवान थाईलैंड मलेशिया कंबोडिया सिंगापुर इंडोनेशिया बांग्लादेश स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जैसे देश भी शामिल हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह कदम केवल किसी एक देश के खिलाफ नहीं बल्कि व्यापक वैश्विक व्यापार रणनीति का हिस्सा है।

आने वाले समय में इस जांच की प्रक्रिया के तहत विभिन्न देश और कंपनियां अपनी दलीलें प्रस्तुत करेंगे। मार्च से इस प्रक्रिया की शुरुआत होगी और मई में सुनवाई के बाद अमेरिका कोई फैसला ले सकता है। यदि अमेरिका को अपने आरोपों के समर्थन में पर्याप्त आधार मिल जाता है तो वह इन देशों पर नए टैरिफ लागू कर सकता है।

फिर भी कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह पूरी प्रक्रिया वास्तव में दबाव की रणनीति हो सकती है जिसका उद्देश्य व्यापारिक वार्ता में बेहतर शर्तें हासिल करना है। अमेरिका अक्सर इस तरह की जांच और टैरिफ की धमकी का उपयोग अपने व्यापारिक साझेदारों को बातचीत की मेज पर लाने के लिए करता रहा है।

भारत के लिए इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि वह अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए मजबूत कूटनीतिक और आर्थिक रणनीति अपनाए। भारत को अपने निर्यात बाजारों का विविधीकरण करना होगा और घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को और मजबूत बनाना होगा। साथ ही वैश्विक व्यापार नियमों के तहत अपने अधिकारों की रक्षा करना भी जरूरी होगा। अंततः यह स्पष्ट है कि वैश्विक व्यापार का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। बड़े देश अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए नए नए औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के सामने चुनौती यह है कि वे इन दबावों के बीच भी अपनी विकास यात्रा को जारी रखें और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मजबूत जगह बनाएं।

कांतिलाल मांडोत

युद्ध और आम नागरिक

एक तरफ जहां पश्चिम एशिया में ईरान-इजराइल व अमेरिका युद्ध को लेकर भयंकर हाहाकार मचा हुआ है और पूरी दुनिया भीषण आर्थिक झंझावतों से जूझने के कगार पर पहुंच गई है तो भारत में संसद का सत्र चालू है जिसमें इस मामले को लेकर विदेश मन्त्री श्री एस. जयशंकर बयान दे चुके हैं कि भारत कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहा है और वह हर मामले का शान्तिपूर्ण हल चाहता है परन्तु युद्ध की विभीषिका इतनी प्रबल होती है कि चाहे-अनचाहे वह दुनिया के विभिन्न शान्ति प्रिय देशों को भी अपनी चपेट मे लेने की क्षमता रखती है। अतः भारत में पश्चिम एशिया के युद्ध के जो विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं उसे हम सब देख रहे हैं। इस मामले में अभी तक सबसे बड़ा बुरा असर ईंधन गैस की सप्लाई पर पड़ा है और पूरे देश में इसकी किल्लत महसूस की जाने लगी है परन्तु इसके लिए सीधे सत्तारूढ़ सरकार को दोषी बता देना भी कदापि उचित नहीं है क्योंकि भारत 80 प्रतिशत से अधिक ईंधन गैस की आपूर्ति आयात द्वारा ही करता है।

पश्चिम एशिया का युद्ध अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां युद्ध के सभी नियम धराशायी हो रहे हैं और ईरान व इजराइल तथा अमेरिका एक-दूसरे की ताकत को खत्म कर देने की कोशिश में सभी नैतिक मानदंडों को ताक पर रख रहे हैं जिसकी वजह से पूरे विश्व में पेट्रोलियम कच्चे तेल की सप्लाई रुक जाने के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। इस मामले में सबसे पहले यह समझना होगा कि यह लड़ाई पूरी तरह गैर संवैधानिक व नियम विरुद्ध है जो अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रम्प की जिद की वजह से शुरू हुई है। श्री ट्रम्प ने युद्ध शुरू करते हुए अपना लक्ष्य बताया था कि वह ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। इस क्रम में उन्होंने ईरान पर हमला करके उसके सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या तक कर दी परन्तु ईरान में वहां की राष्ट्रवादी जनता ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला माना और वह ईरान की सत्ता पर काबिज दूसरी पंक्ति के नेताओं के पीछे चलने लगी। इसके बाद ईरान ने इस युद्ध में अपनी पूरी सामरिक शक्ति व सामर्थ्य को झोंकते हुए पूरे खाड़?ी व पश्चिम एशियाई इलाकों के विभिन्न देशो में स्थापित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला करना शुरू किया और अपने नियन्त्रण में होर्मुज के जलडमरू मध्य के समुद्री मार्ग को एक हथियार बनाना शुरू किया जिससे पूरी दुनिया का 20 प्रतिशत से अधिक कच्चे तेल का दुनिया के विभिन्न देशों को यातायात किया जाता है। अब इस जलडमरू मध्य से ईरान केवल कुछ गिने-चुने देशों के जहाजों को छोड़ कर अन्य देशों के जहाजों को गुजरने नहीं दे रहा है और चेतावनी दे रहा है कि यदि ऐसा करने का प्रयास किन्हीं अन्य देशों ने किया तो उसके गंभीरतम परिणाम होंगे।

युद्ध में जब ऐसा मुकाम आता है तो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक व रणनीतिक समीकरण बदलने लगते हैं। अतः हम आज जो कुछ भी होर्मुज जलडमरू मध्य में देख रहे हैं वह केवल युद्ध के दुष्परिणाम ही हैं। जहां तक खाड़ी व अरब देशों का सवाल है तो वे भी इस युद्ध में अमेरिका के सहयोगी बने रहने का परिणाम भुगत रहे हैं। मगर इस युद्ध से केवल कच्चे तेल के भाव ही प्रभावित हों ऐसा नहीं है क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक पोतों का मुख्य मार्ग है जिसकी वजह से विभिन्न देशों मे अन्य सामान की सप्लाई भी प्रभावित होती है यही वजह है कि भारत में केवल ईंधन गैस की किल्लत होने से ही इसके महानगरों के होटलों व रेस्टोरेंटों के व्यापार में भारी गिरावट दर्ज हो रही है। इतना ही समुद्री व्यापारिक मार्गों के अवरुद्ध होने की वजह से अन्य वस्तुओं पर भी परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा है।

अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारत इस संकट का मुकाबला किस प्रकार करे? जहां तक कच्चे तेल का सवाल है तो भारत ने रूस से इसका आयात बढ़ा दिया है और अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की आपूर्ति करने के लिए विश्व के दूसरे उत्पादक देशों के साथ अनुबन्ध करने शुरू कर दिये हैं। इसके साथ यह भी समझना जरूरी है कि इस अनचाहे संकट का हम भारतवासी किस प्रकार मुकाबला करें जिससे हमारे कष्ट कम से कम हो सकें। इस सन्दर्भ में हमारी संसद के चल रहे सत्र का महत्व बहुत अधिक हो जाता है क्योंकि पूरी संसद समवेत स्वर में कह सकती है कि मौजूदा सरकार को केवल अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च रखते हुए ऐसी नीति का अनुसरण करना चाहिए जिससे आम भारतीयों को कम से कम कष्ट भोगना पड़े। बेशक भारत में बहुदलीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है परन्तु इसका मुख्य ध्येय केवल आम नागरिक का बहुआयामी विकास ही है।

विकल्पहीन मजबूरी है ईच्छा मृत्यु से जीवन के अंत का फैसला

यूं तो देश की अदालतें हर साल तकरीबन सौ से अधिक मुलजिमों को फांसी की सजा सुनाती हैं तब न्याय की कुर्सी पर बैठे किसी जज को कोई ग्लानि या अफसोस नहीं होता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक ऐसा फैसला दिया जिसे लिखते हुए उनकी आंखें सजल हो गई क्यों कि यह फैसला एक जीवन से जंग लड़ रहे इंसान को कष्ट मुक्ति के लिए मौत की ओर सहयोग करने का है। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने एक अभूतपूर्व फैसले में इच्छामृत्यु को मंजूरी दी है। अदालत ने 32 साल के हरीश राणा के लिए इच्छामृत्यु की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट में जब जस्टिस जे. बी. पारदीवाला यह फैसला सुना रहे थे तो इस दौरान वे बेहद भावुक हो गए और उनकी आंखें नम हो गई थी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने हरीश राणा के माता-पिता को उनकी जीवनरक्षक चिकित्सा हटाने की इजाजत दे दी है। हरीश राणा पिछले 13 साल से लगातार वेजिटेटिव स्टेट यानी कोमा में हैं। अपना फैसला पढ़ते समय जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि हरीश राणा कभी एक होनहार छात्र थे और अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन एक दुर्घटना ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे मामलों में मुख्य सवाल यह नहीं होता कि मरीज के लिए मौत बेहतर है या नहीं, बल्कि यह देखा जाना चाहिए कि जीवन को बनाए रखने वाला इलाज मरीज के हित में है या नहीं। अदालत ने कहा कि हरीश राणा में सिर्फ सोने जागने के चक्र में फंसे हुए हैं, लेकिन वह किसी भी तरह की अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं। वह अपने दैनिक कामों के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हैं। अदालत ने यह भी बताया कि हरीश को पीईजी ट्यूब के जरिए क्लिनिकली एडमिनिस्टरड न्यूट्रिशन दिया जा रहा है और इतने सालों में उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। जब एक इंसान का जीवन इतना कष्ट मय और लाइलाज हो जाए कि मौजूदा तमाम मेडिकल उपचार अनुपयोगी हो जाए और क्षण क्षण तड़प रही जिंदगी को कष्ट से बचाने का कोई उपाय न रहे तब जीवन से मुक्ति के लिए मौत ही एक मात्र विकल्प रह जाता है मौजूदा घटनाक्रम के अनुसार 20 अगस्त 2013 को हरीश राणा अपने छात्रावास की चौथी मंजिल से गिर गए थे। उनके सिर में गहरी चोट लगी और लंबे इलाज के बावजूद वे कोमा से निकल नहीं पाए हैं। उनकी स्थिति को देखते हुए उनके अभिभावकों ने ही इच्छामृत्यु की प्रार्थना की थी। जिस पर दिसंबर 2025 की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा की निष्क्रिय इच्छामृत्यु की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। तब भी अदालत ने कहा था कि हरीश पिछले 13 वर्षों से गंभीर स्थिति में हैं, और उन्हें इस हालत में जीने नहीं दिया जा सकता। हरीश राणा को ट्यूब के जरिए पोषण पहुंचाकर जिंदा तो रखा गया, लेकिन वे किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे थे और लगातार बिस्तर पर होने के कारण उनकी शारीरिक अवस्था भी सही नहीं थी। उनकी चिकित्सा रिपोर्टर्स में इन सारी तकलीफों का विस्तार से वर्णन किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली में एम्स के चिकित्सकों के द्वितीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा दाखिल की गई राणा की चिकित्सा संबंधी रिपोर्ट का अवलोकन किया था और कहा था कि यह रिपोर्ट' दुखद' है।

प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड ने मरीज की स्थिति की जांच करने के बाद कहा था कि उसके ठीक होने की संभावना नगण्य है। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल 11 दिसंबर को मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार यह व्यक्ति' बेहद दयनीय स्थिति' में है। पीठ ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को राणा को उपशामक देखभाल इकाई में भर्ती करने का निर्देश दिया है ताकि चिकित्सकीय उपचार बंद किया जा सके। पीठ ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उपचार को एक सुनियोजित तरीके से बंद किया जाए ताकि गरिमा बनी रहे। आमतौर पर यही कहा जाता है कि जब आप किसी व्यक्ति को जीवन दे नहीं सकते, तो जीवन लेने का हक भी आपको नहीं है। कई देशों में इसी आधार पर मृत्युदंड पर भी बहस छिड़ी रहती है, क्योंकि एक बार सांसों की डोर टूट गई, तो फिर उसे जोड़ने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर व्यक्ति जिंदा होकर भी किसी मृतप्राय व्यक्ति की तरह हो जाए, जिसके लिए कोई इलाज कारगर न साबित हो, जो असहनीय तकलीफों से गुजरे तो क्या उसे इच्छामृत्यु की इजाजत दी जा सकती है। तब क्या इसे हत्या या आत्महत्या या मृत्युदंड से अलग न्यायोचित ठहराया जा सकता है। ऐसे कई सवाल इच्छामृत्यु के फैसले पर उठते रहे हैं।

बुधवार को आए इस फैसले के बाद सम्मानजनक मृत्यु के अधिकार यानी 'राइट टू डाई विद डिग्निटी' जैसे अहम सवाल पर नयी चर्चा शुरु हो सकती है। दरअसल भारत में ऐसा ही एक मामला 1973 में आया था, जब मुंबई के केईएम अस्पताल के वार्डबॉय सोहनलाल वाल्मीकि ने नर्स अरुणा शानबाग के साथ बेरहमी से यौन उत्पीड़न किया और गला दबाया था, जिससे वे स्थायी रूप से कोमा में चली गई थी। उनके माता-पिता नहीं थे और इस घटना के बाद परिजनों ने भी उनका त्याग कर दिया था। मगर अस्पताल की साथी नर्सों ने उन्हें कोमा में होने के बावजूद जीवित रखने की पूरी कोशिश की। 2009 में पत्रकार पिंकी विरानी ने उनकी दर्दनाक हालत को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय में इच्छा मृत्यु की याचिका दायर की थी, अदालत ने 7 मार्च 2011 को याचिका खारिज कर दी थी, क्योंकि उनका इलाज करने वाली नर्सें और डॉक्टर उन्हें जीवित रखने के लिए प्रतिबद्ध थे। हालांकि, कोर्ट ने 'पैसिव यूथेनेशिया' लाइफ सपोर्ट हटाना को अनुमति दी, जिसमें कहा गया कि जब तक मरीज की हालत सुधरने की उम्मीद न हो, तब तक यह लिया जा सकता है। इसके बाद 18 मई 2015 को निमोनिया के कारण अरुणा शानबाग का निधन हो गया। हालांकि 42 वर्ष तक कोमा में रहने का कष्ट उन्होंने सहा है।

इस मामले ने भारत में 'गरिमापूर्ण मृत्यु से संबद्ध कानून की एक नई पहल हुई है अरुणा शानबाग मामले के बाद इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून की जरूरत महसूस की जाने लगी। इसी मुद्दे को लेकर कॉमन कॉज़ नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च 2018 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018) सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला था, जिसने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। इसके अलावा अदालत ने लिविंग विल का अधिकार दिया। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति पहले से लिखकर यह तय कर सकता है कि अगर वह भविष्य में ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां वह खुद निर्णय लेने की स्थिति में न हो, तो उसे कृत्रिम लाइफ सपोर्ट पर न रखा जाए। हालांकि, कॉमन कॉज़ मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु कब लागू की जा सकती है, इस पर दिशा-निर्देशों को पूरी तरह से निर्धारित और स्पष्ट नहीं किया जा सका। मगर अब हरीश राणा के मामले में इस फैसले को आधार माना गया है।उस परिवार और माता-पिता की पीड़ा को समझना कितना दुखद है जो एक दुखद अनहोनी के बाद अपनी ही युवा संतान के लिए मौत की भीख मांगने के लिए मजबूर हुए हैं ईश्वर ऐसी वारदातों की पुनरावृत्ति न हो।

मनोज कुमार अग्रवाल

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर परगना खैराबाद तहसील व जनपद -सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः**-उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादो का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। **R.N.I NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0 -9511151254,**E-Mail :- news@swatantraprabhat .com

संक्षिप्त खबरें

रमजान माह में जुमे की नमाज अदा, अमन-चैन और खुशहाली की मांगी दुआ

मस्जिदों में उमड़ी नमाजियों की भीड़, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस रही मुस्तैद

लालगंज (रायबरेली)। पवित्र रमजान माह के दौरान शुक्रवार को कस्बा सहित आसपास के क्षेत्रों में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने जुमे की नमाज अदा की। मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर देश और समाज में अमन-चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के दौरान कस्बे का माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण बना रहा। कस्बे की चिक मंडी स्थित जामा मस्जिद, कांचमील मस्जिद, बड़ी मस्जिद, मोहम्मदिया मस्जिद और अल्ला नगर स्थित मस्जिद सहित अन्य इबादतगाहों में नमाज अदा करने के लिए दोपहर से ही नमाजियों का पहुंचना शुरू हो गया था। नमाज के समय मस्जिदों में काफी भीड़ रही। लोगों ने रमजान की बरकत और समाज में आपसी सौहार्द बनाए रखने की दुआ की। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क रहा। जुमे की नमाज को देखते हुए मस्जिदों और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किया गया। प्रमुख स्थानों पर पुलिस कर्मी मुस्तैदी से ड्यूटी करते दिखाई दिए। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

लहरपुर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन, सैकड़ों मरीजों को मिला उपचार

विशेषज्ञ डॉक्टरों ने 300 से अधिक मरीजों की जांच कर दी दवाइयां, 65 लोगों की हुई रक्त जांच

लहरपुर सीतापुर(संवाद)। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन आफ इंडिया श्री पीतांबरा शिक्षा समिति एवं केपी सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल पारा सराय के संयुक्त तत्वाधान में एक फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप का आयोजन लहरपुर के शाह मज़ा कलंदर की दरगाह के सामने मजाशाह मे आयोजित किया गया शिविर में क्षेत्र के गरीब जरूरतमंद व लहरपुर के लोगों ने निशुल्क चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाया चिकित्सा शिविर में वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर एस ए मीर एमडी मेडिसिन ने 178 रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयां दी और उनकी जांच कराई गई तथा डॉक्टर मधुलिका राय ने महिलाओं में बाझपन लिकोरिया एवं माहवारी से जुड़ी 32 महिलाओं में बीमारियों की जांच कर निशुल्क दवाइयां दी गई इसके अलावा डॉक्टर हर्षित जैन के द्वारा 52 रोगियों का परीक्षण कर उन्हें दवाइयां दी गई डॉ सौरभ सिंह सर्जन के द्वारा 47 रोगियों का परीक्षण कर उनको दवाइयां दी गयी कैंप में डॉक्टर निशा गौतम गाईनी स्पेशलिस्ट के अलावा नर्स स्टाफ व मेडिकल टीम के लोग उपस्थित रहे कैंप में 65 लोगों का रक्त जांच भी किया गया कार्यक्रम में अंशुमान सिंह ऐश्वरय प्रताप सिंह मोहम्मद ताहिर मोहम्मद अरशद शाही इमाम कारी अनवार आलम साहब मोहम्मद हसीन अंसारी के अलावा शहर के सम्मानित नागरिक उपस्थित रहे।

नल से जल कनेक्शन देने में यूपी देश में किस नंबर पर? जलशक्ति मंत्री ने दी जानकारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश, देश में सबसे अधिक नल से जल कनेक्शन देने वाला राज्य बन गया है। जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शुक्रवार को जल जीवन मिशन 2.0 को लेकर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल द्वारा सभी राज्यों के साथ की गई वर्चुअल बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2.43 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि विंध्य-बुंदेलखंड क्षेत्र में 95 प्रतिशत से अधिक घरों तक नल से जल की सप्लाई की जा रही है। 100 प्रतिशत जलापूर्ति वाले गांवों में जल अर्पण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिसमें जलापूर्ति की पूरी व्यवस्था ग्राम पंचायत को हैंडओवर की जा रही है। बैठक में केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय के अधिकारियों ने जल जीवन मिशन-2.0 की रूपरेखा सभी राज्यों के सामने रखी। बताया गया कि भविष्य में किस तरह से योजना को लेकर कार्य किया जाना है। इसमें केंद्र और राज्य की क्या भूमिका होगी। साथ ही राज्यों से सुझाव मांगे गए कि योजना को किस तरह से बेहतर ढंग से जमीन पर उतारा जा सकता है। बैठक में उप से अपर मुख्य सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग अनुराग श्रीवास्तव ने भी प्रतिभाग किया।

'स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता' विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया

स्वतंत्र प्रभात

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), उत्तर प्रदेश राज्य केंद्र, लखनऊ द्वारा 13 मार्च 2026, शुक्रवार को इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स भवन, आई.ई.आई., रीवर बैंक कॉलोनी, लखनऊ में 'स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस इन हैल्थकेयर) विषय पर एक महत्वपूर्ण तकनीकी व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. सचिन कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, एमिटी स्कूल ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एमिटी यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश ने उपस्थित सदस्यों को स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के योगदान, नवीनतम तकनीकी प्रगति और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत जानकारी दी। अपने व्याख्यान में उन्होंने एआईआधारित रोग पहचान, उपचार में सुधार, डेटा विश्लेषण, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रबंधन में इसके उपयोग पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। डॉ. कुमार ने यह भी बताया कि कैसे एआईतकनीक से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है, रोगियों के लिए अधिक सटीक और त्वरित उपचार सुनिश्चित किया जा सकता है, और स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि एआई आधारित तकनीकों की सहायता से डॉक्टरों को निर्णय लेने में सहायता मिलती है, जिससे गंभीर बीमारियों का समय रहते पता लगाया जा सकता है और मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, रोबोटिक सर्जरी और स्मार्ट हेल्थकेयर सिस्टम जैसे क्षेत्रों में भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ, तेज और प्रभावी बन रही हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता इं. वी.पी. सिंह, अध्यक्ष, आई.ई.आई. उत्तर प्रदेश राज्य केंद्र, लखनऊ द्वारा की गई। अपने अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस इन हैल्थकेयर) के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अभियंता और तकनीकी विशेषज्ञ इस क्षेत्र में नवाचार, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और रोगियों के बेहतर उपचार के माध्यम से समाज के स्वास्थ्य स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के संयोजक डॉ. ए.के. जौहरी ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए इसका सफल संचालन किया। उन्होंने मुख्य वक्ता डॉ. सचिन कुमार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्था भविष्य में भी ऐसे ज्ञानवर्धक और जनोपयोगी कार्यक्रमों का आयोजन करती रहेगी, जो स्वास्थ्य और तकनीकी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा दें। संस्था के माननीय सचिव इं. नीरेन्द्र कुमार निषाद ने सभी उपस्थित अतिथियों, अभियंताओं, शिक्षाविदों एवं छात्रों का स्वागत और धन्यवाद ज्ञापन किया। इस आयोजन ने इंजीनियरिंग और हेल्थकेयर के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका को समझने और आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। उपस्थित सभी सदस्यों ने इस पहल की सराहना की और भविष्य में इस तरह के ज्ञानवर्धक और जनोपयोगी कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया।

हाउस टैक्स वसूली में नगर निगम की बड़ी सफलता, 1.12 करोड़ रुपये जमा

स्वतंत्र प्रभात

लखनऊ। नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में हाउस टैक्स वसूली अभियान तेज कर दिया गया है। नगर आयुक्त के निर्देश पर जोन-3 में चलाए गए अभियान के दौरान नगर निगम की टीम ने कुल 1 करोड़ 12 लाख रुपये का बकाया गृहकर वसूल कर नगर निगम के राजकोष में जमा कराया।

जानकारी के अनुसार जानकीपुरम स्थित आकांक्षा परिसर से ही करीब 1 करोड़ रुपये का बकाया हाउस टैक्स जमा कराया गया। यह कार्रवाई जोनल अधिकारी आकाश कुमार के नेतृत्व में की गई, जिसमें कर अधीक्षक आलोक श्रीवास्तव और राजस्व निरीक्षक मोहज्जिब ने टीम के साथ मिलकर अभियान चलाया।

इसके अलावा नगर निगम की टीम ने अन्य वार्डों में भी बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 12 लाख रुपये का अतिरिक्त गृहकर जमा कराया। अधिकारियों का कहना है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले बड़े बकायेदारों से वसूली के लिए विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा।

नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय से अपना गृहकर जमा कर दें, अन्यथा बकायेदारों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दबिश के दौरान 38 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद लगभग 150 किलोग्राम लहन मौके पर नष्ट, 02 अभियोग पंजीकृत

रायबरेली:- जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देशानुसार अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी के विरुद्ध जारी विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत जिला आबकारी अधिकारी के कुशल नेतृत्व में, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-3 की टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर दबिश की कार्यवाही की गयी। टीम द्वारा तहसील लालगंज के थाना खीरों अंतर्गत ग्राम महारानीगंज एवं नंदा खेड़ा में अवैध कच्ची शराब बनाने के अड्डों/संदिग्ध घरों पर दबिश की कार्यवाही की गई। दबिश के दौरान 38 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई तथा लगभग 150 किलोग्राम लहन बरामद कर मौके पर नष्ट करते हुए 02 अभियोग आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किये गए। जिले में अवैध शराब के निर्माण एव बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु इस तरह की कार्यवाही आगे भी जारी रहेंगी।

दबिश के दौरान 38 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद लगभग 150 किलोग्राम लहन मौके पर नष्ट, 02 अभियोग पंजीकृत

रायबरेली:- जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देशानुसार अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी के विरुद्ध जारी विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत जिला आबकारी अधिकारी के कुशल नेतृत्व में, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-3 की टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर दबिश की कार्यवाही की गयी। टीम द्वारा तहसील लालगंज के थाना खीरों अंतर्गत ग्राम महारानीगंज एवं नंदा खेड़ा में अवैध कच्ची शराब बनाने के अड्डों/संदिग्ध घरों पर दबिश की कार्यवाही की गई। दबिश के दौरान 38 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई तथा लगभग 150 किलोग्राम लहन बरामद कर मौके पर नष्ट करते हुए 02 अभियोग आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किये गए। जिले में अवैध शराब के निर्माण एव बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु इस तरह की कार्यवाही आगे भी जारी रहेंगी।

जेल से रिहा युवक लापता, परिजनों ने एसपी से लगाई गुहार

● दो माह से घर नहीं लौटा

स्वतंत्र प्रभात

सुल्तानपुर- जेल से रिहा होने के बाद एक युवक पिछले दो माह से लापता है। उसके परिजन उसकी तलाश कर रहे हैं और बेटे का पता लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। हलियापुर निवासी मनीराम ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर अपने पुत्र हरिकेश का पता लगाने की मांग की है। मनीराम के अनुसार, उनका बेटा आबकारी अधिनियम के तहत एक मामले में वांछित था। गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने उसे 4 जनवरी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था।

पिता मनीराम ने बताया कि 6 जनवरी को उनके बेटे ने कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया। मनीराम का आरोप है कि जब वे बेटे को लेने जेल पहुंचे तो उन्हें अगले दिन आने को कहा गया। अगले दिन पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि हरिकेश को एक दिन पहले ही रिहा कर दिया गया था, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा।

परिजनों ने यह भी बताया कि उनका बेटा 15 वर्ष पुराने एक मामले में जेल से जमानत पर छूटने के बाद कानपुर चला गया था। पेशी पर उपस्थित न होने के कारण न्यायालय से उसके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया गया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस संबंध में जेलर ओंकार पाण्डेय ने जानकारी दी कि 6 जनवरी को कुल 14 आरोपित रिहा किए गए थे, जिनमें हरिकेश भी शामिल था। वहीं, थानाध्यक्ष वंदना अग्रहरि ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में है और युवक की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

आरपीएम पब्लिक स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम

● नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुति ने लोगों को किया मंत्र मुग्ध

● धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव समारोह

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लंभुआ। सुल्तानपुर लंभुआ नगर पंचायत क्षेत्र के अटल नगर वार्ड में स्थित आरपीएम पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव समारोह धूमधाम से मनाया गया। मंच पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर छात्र-छात्राओं ने छटा बिखेर दी। कार्यक्रम में शामिल सभी छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह ने मौजूद प्रतिभाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। भाजपा नेता विकास वर्मा ने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ छात्र-छात्राओं के जीवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी आवश्यकता है। सेवार्थम फाउंडेशन के संस्थापक आशीष तिवारी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों की प्रतिभा को निखारने के साथ-साथ शिक्षा और सामाजिक संदेश देने का मंच बनते हैं। भाजपा नेता अवनीश कुमार गुड्डू सिंह ने बच्चों को आगे बढ़ने एवं लक्ष्य की प्राप्ति करने के कुछ टिप्स बताए। भाजपा नेत्री श्रीमती रेखा बरनवाल ने बच्चों का हौसला आफजाई करते हुए प्रतिभाओं का सम्मान किया। मौके पर एमएलसी प्रतिनिधि डिंपल सिंह, एबीएसए अजय सिंह, कोतवाली प्रभारी धीरज कुमार,ईओ अमित सिंह, सपा नेता नवनीत यादव, प्रधान संघ अध्यक्ष कैलाश द्विवेदी, किसान नेता प्रभात सिंह, गिरीश पांडे, रणवीर सिंह, केदारनाथ दूबे, डॉ रामकरन वर्मा, प्राचार्य डॉ मंजू मगन, पूर्व ब्लाक प्रमुख प्रमोद सिंह, डॉ रामअभिलाष सिंह, गौरी शंकर पांडे, हिमांशु सिंह, देवेंद्र पांडे, रामतीर्थ सिंह, आशीष सिंह, नीरज शर्मा, रत्नेश वैश्य, बृजलाल यादव आदि मौजूद थे।

ओथी ग्राम सभा में आनंद मिश्रा द्वारा संकल्पित छठवीं श्रीमद्भागवत कथा का हो रहा भव्य आयोजन

● कलश को सिर पर धारण करने से आत्मा पवित्र हो जाती है- कथा व्यास

स्वतंत्र प्रभात

महराजगंज/रायबरेली। तहसील क्षेत्र के ओथी ग्राम सभा में शुक्रवार को श्रीमद्भागवत कथा के प्रारंभ से पूर्व गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों व बच्चों ने भाग लिया। सभी ने सिर पर कलश रखकर गांव सहित आस पास के मुख्य मार्गों से होते हुए देवालयों में पहुंची जहां सभी ने मत्था टेका।

विदित हो कि क्षेत्र के ग्राम सभा जिहवा के रहने वाले आनंद मिश्रा द्वारा संकल्पित छठवीं श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन ओथी ग्राम सभा में यजमान आशीष मौर्य के यहां प्रथम दिन शुक्रवार को सिधौना अमांवा से पधारी कथा व्यास संध्या जी भागवत कथा में माहात्म और धुंधकारी महाराज की विविध कथाओं का वर्णन कर कथा पडाल में उपस्थित समस्त श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। इस मौके पर यज्ञ शाला के मुख्य यज्ञाचार्य पंडित योगेंद्र तिवारी,उपयज्ञाचार्य अमरेश शुक्ला, पंडित अरूण त्रिपाठी, सोनू मौर्य, अवधेश मौर्य, शांत प्रसाद, बब्लू प्रजापति, संकठा प्रसाद, बाबा जयजयराम, दिनेश कोटेदार, शिव कुमार, कन्हैया मौर्य, शिव प्रसाद सहित आदि भक्त उपस्थित रहे।

जहांगीराबाद में शनिवार को लगेगा विद्युत समाधान शिविर

बिसवां (सीतापुर)। विद्युत वितरण उप खण्ड सांडा द्वारा बिजली से सम्बंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए शनिवार 14 मार्च को एक विद्युत शिविर का आयोजन क्षेत्र के जहांगीराबाद स्थित श्री राम मनोहर श्रीवास्तव स्मारक विद्यालय के प्रांगण में प्रातः 9 बजे से किया जा रहा है जिसमें बिजली उपभोक्ता अपनी समस्याओं के समाधान के साथ साथ बिजली बिलों को भी जमा कर सकेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए अवर अभियंता सुरेश चन्द्र ने बताया कि जब से नये स्मार्ट मीटर लगाये गये हैं तब से उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने में उहापोह की स्थिति बनी हुई है जिस कारण शनिवार को विद्युत समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है जहां उपभोक्ता परामर्श के साथ अपनी बिजली से सम्बंधित समस्याओं/शिकायतों का समाधान कराकर अपना बिल भी जमा कर सकेंगे।

खाटू श्याम भक्तों ने 1400 किमी की पदयात्रा शुरू की, सालासर धाम के लिए हुए रवाना

● गाजे-बाजे और फूल-मालाओं के साथ श्रद्धालुओं को दी गई विदाई, नगरवासियों ने की यात्रा की सफलता की कामना

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज (रायबरेली)। कस्बे के घोसियाना मोहल्ले से शुक्रवार को खाटू श्याम भक्तों ने सालासर धाम तक करीब 1400 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की। यात्रा पर निकलने से पहले श्रद्धालुओं को गाजे-बाजे और फूल-मालाओं के साथ भावभीनी विदाई दी गई। नगरवासियों ने उनकी यात्रा की सफलता और सुरक्षित वापसी की कामना की।

नगर निवासी खाटू श्याम भक्त अंकित अग्रहरि और सुजल जायसवाल ने इस धार्मिक पदयात्रा की शुरुआत की। यात्रा शुरू करने से पहले दोनों श्रद्धालु बरदाही मोहल्ला स्थित खाटू श्याम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान खाटू श्याम के दर्शन कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और आशीर्वाद लिया।

इसके बाद दोनों श्रद्धालु सालासर धाम के लिए पैदल रवाना हो गए। सुजल जायसवाल ने बताया कि वे करीब 1400 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर सालासर धाम पहुंचेंगे।

यात्रा की शुरुआत के दौरान मोहल्ले और नगर के लोगों ने दोनों भक्तों का उत्साहवर्धन किया। श्रद्धालुओं को फूल-मालाएं पहनाकर विदा किया गया। इस अवसर पर राजकुमार जायसवाल, पंकज जायसवाल, ज्योति जायसवाल, संजय अग्रहरि, मीना अग्रहरि और सुशील सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का किया गया आयोजन

स्वतंत्र प्रभात

बिसवां (सीतापुर) आज बिसवां ब्लॉक के सुखावां कला ग्राम पंचायत में HCL Foundation के द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला किसानों के साथ-साथ स्वयं सहायता समूह (SHG), ग्राम संगठन तथा छात्रा से लगभग 300 महिलाओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में ब्लॉक स्तर के कई अधिकारी एवं अतिथि उपस्थित रहे, जिनमें NRLM से गुलशन तिवारी (BMM) एवं संगीता, सदर पुलिस स्टेशन से कामिनी एवं सपना, एसआई रामचरन यादव, CHO रोली जायसवाल, BOC स्वेता वर्मा, ग्राम सचिव कनकलता तथा CLF सचिव अंजू देवी शामिल रहीं। इसके साथ ही चयनित 5 ग्राम पंचायतों की महिला प्रधान भी कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता HCL Foundation के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कमलेश कुमार ने की। उन्होंने HCL Foundation और उसकी माटी परियोजना एवं महिला दिवस के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर पुलिस विभाग से आई कामिनी एवं सपना ने महिलाओं की सुरक्षा, नारी शक्ति और सरकार द्वारा चलाई जा रही सुरक्षा संबंधी सेवाओं की जानकारी देते हुए अपने संपर्क विवरण भी साझा किए। वहीं BOC स्वेता वर्मा ने महिलाओं को स्वास्थ्य, टीकाकरण और संतुलित खान-पान के बारे में जानकारी दी।

गुलशन तिवारी (BMM, NRLM) ने महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रखने और समूह के माध्यम से आजीविका बढ़ाने के विभिन्न अवसरों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम के दौरान चयनित 5 ग्राम पंचायतों के एक-एक स्वयं सहायता समूह को संस्था द्वारा विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र भी प्रदान किए गए, जिससे महिलाओं की कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। इस अवसर पर HCL Foundation की टीम से कमलेश कुमार, रामकुमार, जावेद अख्तर, वीरेंद्र कुमार, अमित, अमरजीत, अनुराग, संतोष, क्षमा, लक्ष्मी, प्रीति सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

चोरों ने बन्द घर को बनाया निशाना हजारों का सामान लेकर हुए फरार

स्वतंत्र प्रभात
जो लिखेगा, वही टिकेगा
ब्रेकिंग न्यूज़

बिसवां सीतापुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मतिकपुर में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को असलहे के दम पर अनुप यादव के घर में लूटपात की थी दूसरे दिन चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए हजारों का सामान पार कर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत और आक्रोश का माहौल है। गांव के बाहर स्थित लालजी यादव के फार्म हाउस में चोरों ने घर के गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और घर में रखा इनवर्टर, बैटरी सहित अन्य सामान उठा ले गए। पीड़ित लालजी यादव ने बताया कि वह रात में अपने नतीन का तिलक ले कर गए हुए थे। सुबह जब वह वापस अपने फार्म हाउस पहुंचे तो घर का ताला टूटा देखकर उनके होश उड़ गए और चोरी की घटना का पता चला। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस व डायल 112 मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच पड़ताल शुरू कर दी। घटना से नाराज गांव के करीब 15- 20 ग्रामीण कोतवाली पहुंचकर प्रभारी निरीक्षक से मिले। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही घटना का खुलासा कर चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा।

महिला आयोग की सदस्य ने महिला उत्पीड़न से संबंधित सुनीं शिकायतें

● महिला आयोग की सदस्य ने महिलाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को जन-जन तक पहुचाने के लिए दिये निर्देश

महिला जनसुनवाई में प्राप्त हुई 25 शिकायते

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रायबरेली:- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के उपलक्ष्य में उ0प्र0 राज्य महिला आयोग की सदस्य पुनम द्विवेदी ने जिला पंचायत सभागार में महिला उत्पीड़न व उनकी समस्याओं से जुड़े मुद्दो के बारे में अधिकारियों से समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने जन सुनवाई करते हुए घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, वैवाहिक समस्या, लैंगिक भेदभाव, शिक्षा व रोजगार आदि संबंधी शिकायत सुनी। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए पीड़ित महिलाओ को शीघ्र न्याय दिलाया जाए। निर्देश दिये कि महिलाओं के उत्पीड़न व महिला से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक एवं समयबद्ध तरीके से किया जाये तथा महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार ग्राम पंचायत व ग्रामीण स्तर पर कराया जाये। जिन प्रकरणों में अभी कार्यवाही लंबित है उन्हें भी आयोग के संज्ञान में लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देश है कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित प्रकरणों में शीघ्र कार्रवाई की जाए। महिला जन सुनवाई के दौरान 25 शिकायत प्राप्त हुई जिन्हें शीघ्र निस्तारित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि पीड़ित महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। महिला आयोग सदस्य ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं न्याय सुनिश्चित करना राज्य महिला आयोग की प्राथमिकता है और किसी भी पीड़िता के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

इस मौके पर जिला प्रोबेशन अधिकारी जयपाल वर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव कुमार सिंह, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मोहन त्रिपाठी, जिला विधिक सेवा प्राधिकारण के अधिकारियों सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

सीतापुर के आचार्यों ने सिक्किम में प्रस्तुत किए शोधपत्र

» ए.एन.डी. टीचर्स ट्रेनिंग पीजी कॉलेज के प्राध्यापकों की राष्ट्रीय संगोष्ठी में सहभागिता

» IATE के वार्षिक अधिवेशन में सीतापुर के शिक्षाविदों का शोधपत्र प्रस्तुतीकरण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर। ए.एन.डी. टीचर्स ट्रेनिंग पीजी कॉलेज, सीतापुर के प्राध्यापक प्रो. सुनील कुमार एवं प्रो. प्रनिता सिंह ने सिक्किम के गंगटोक स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर एजुकेटर्स (IATE) के वार्षिक अधिवेशन में अपने शोधपत्र प्रस्तुत किए।

इस अवसर पर दोनों आचार्यों ने तकनीकी सत्रों की अध्यक्षता भी की। राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षाविद, शोधार्थी एवं विद्यार्थी शामिल हुए तथा शिक्षक शिक्षा से जुड़े विविध विषयों पर अपने शोधपत्र और विचार प्रस्तुत किए। उल्लेखनीय है कि प्रो. सुनील कुमार इंडियन एसोसिएशन ऑफ

टीचर एजुकेटर्स की उत्तर क्षेत्रीय समिति के सचिव भी हैं। उनके नेतृत्व में नवंबर 2025 में ए.एन.डी. टीचर्स ट्रेनिंग पीजी कॉलेज, सीतापुर में भी राष्ट्रीय संगोष्ठी का सफल आयोजन किया जा चुका है।

संक्षिप्त खबरें

प्राथमिक विद्यालय भगौतीपुर प्रथम में माता अभिभावक संघ की बैठक सम्पन्न

बालिका शिक्षा बहुत आवश्यक है :- पूनम बाजपेई ए आर पी

खैराबाद सीतापुर स्थानीय प्राथमिक विद्यालय भागौतीपुर प्रथम में माता अभिभावक संघ की बैठक का आयोजन प्रधानाध्यापिका प्रतिमा मिश्रा के द्वारा किया गया कार्यक्रम का शुभारंभ ग्राम प्रधान श्रीमती गुडी के द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु विद्यालय में पधारी ए आर पी श्रीमती पूनम जी के द्वारा भी विद्यालय के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर ग्रामीण महिला अभिभावकों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। पूनम बाजपेई ने कहा कि जैसे मनुष्य को जीवित रहने के लिए सांस लेना जरूरी है उसी प्रकार बालिका शिक्षा भी बहुत आवश्यक है। विद्यालय में अधिक से अधिक बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित हो इस हेतु महिला अभिभावकों के समक्ष एक ग्रुप मोनो एक्टिंग वास्तविक जीवन से संबंधित बच्चों के द्वारा प्रस्तुत की गई। मार्च माह में जन्मदिवस वाले बच्चों का जन्मदिन उनकी माताओं के साथ मनाकर भोजन कराया गया। इस कार्यक्रम सेबच्चों की खुशी देखते ही बन रही थी। ये नवाचार निश्चय ही विद्यालय में बच्चों की शत प्रतिशत उपस्थिति को सुनिश्चित करेगा। शिक्षित नारी शिक्षित समाज इसी से होगा देश का विकास इन्हीं शब्दों के साथ प्रधानाध्यापिका प्रतिमा मिश्रा ने ग्राम प्रधान गुड्डी, ए आर पी पूनम बाजपेई जी उपस्थित सभी महिला अभिभावकों का विद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त किया।

प्लेसमेंट ड्राइव छात्रों के पेशेवर दुनिया में जाने के महत्वपूर्ण सफर

बस्ती। बस्ती जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में गुरुवार को प्रशिक्षित डीएलएड प्रशिक्षुओं हेतु प्लेसमेंट ड्राइव एवं करियर काउंसिलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डायट प्राचार्य संजय कुमार शुक्ल ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित करके किया। डीएलएड प्रशिक्षुओ को संबोधित करते हुए डायट प्राचार्य ने कहा कि प्लेसमेंट ड्राइव छात्रों के अकादमिक जगत से पेशेवर दुनिया में जाने के सफर का एक अहम मोड़ होता है। कहा कि प्रदर्शन का दबाव, नए अवसरों का उत्साह और प्रतिस्पर्धा की चिंता इस अनुभव को रोमांचकारी और चुनौतीपूर्ण दोनों बनाती है जीडी गोयनका स्कूल की प्रिंसिपल हुमा वसीम ने कहा कि प्लेसमेंट ड्राइव आपके करियर की शुरुआत मात्र है। इस दौरान आप जो कौशल, दृढ़ता और अनुकूलन क्षमता विकसित करेंगे, वह मनचाही नौकरी मिलने के बाद भी आपके लिए लंबे समय तक उपयोगी साबित होगी। आरएलएमसी स्कूल बस्ती की डायरेक्टर प्रीति खंडेलवाल ने कहा कि आज के समय में करियर के अवसर केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं हैं। निजी क्षेत्र, उद्यमिता, स्टार्टअप, डिजिटल सेवाओं और कौशल आधारित क्षेत्रों में युवाओं के लिए अनेक संभावनाएँ उपलब्ध हैं। युवाओं को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार करियर की योजना बनानी चाहिए। जी डी गोयनका की काउंसलर गुरजीत कौर एवं टीजीटी टीचर मधुबाला ने कहा कि अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना महत्वपूर्ण है, लेकिन याद रखें कि हर कोई सीखने की प्रक्रिया में है। प्रतिक्रियाओं के लिए हमेशा तैयार रहें और हर अनुभव को, चाहे वह सफल हो या असफल, विकास के अवसर के रूप में देखें। कार्यक्रम के नोडल कुलदीप चौधरी और सह नोडल अलीउद्दीन खान ने कहा कि प्लेसमेंट ड्राइव में सफल होने का मतलब पहली ही बार में नौकरी पाना नहीं है, बल्कि अनुभव से सीखना और आगे बढ़ना है। हर परीक्षा, हर बातचीत और हर इंटरव्यू आपके कौशल को निखारता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है इस अवसर पर डायट प्रवक्ता डॉ रविनाथ, डॉ गोविन्द, डॉ ऋचा शुक्ला, अलीउद्दीन खान, शशि दर्शन त्रिपाठी, नवनीत कुमार, अनिल चौधरी आदि उपस्थित रहे।

विजयराघवगढ़ विस के बरही में 'कृषि महोत्सव' की भव्य तैयारी

● मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का होगा ऐतिहासिक स्वागत।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। दया शंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट।

कटनी/ बरही: (एमपी) विजयराघवगढ़। विधानसभा क्षेत्र के लिए आगामी 14 मार्च (शनिवार) का दिन खुशहाली और विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाला है। बरही के श्री विजयनाथ धाम (मेला ग्राउंड) में आयोजित होने वाले विशाल 'कृषि महोत्सव' में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉ. यादव का इस क्षेत्र में यह प्रथम आगमन है, जिसे यादगार बनाने के लिए *विधायक संजय सत्येंद्र पाठक* के नेतृत्व में भव्य तैयारियां की जा रही हैं।

50 हजार एकड़ भूमि के लिए सिंचाई की बड़ी सौगात

इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य हाल ही में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत दो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करना है। इन परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र की लगभग 50,000 एकड़ कृषि भूमि सिंचित हो सकेगी, जिससे 'हर खेत को पानी' का सपना साकार होगा।

कार्यक्रम विवरण।
दिनांकः 14 मार्च 2026, शनिवार
समयः दोपहर 1:30 बजे से
स्थानः श्री विजयनाथ धाम, मेला ग्राउंड, बरही में रैली, कृषि महोत्सव, सिंचाई योजनाओं पर संबोधन और रोड शो।

यह कदम स्थानीय किसानों की आर्थिक समृद्धि और कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।

सुरक्षा और प्रशासनिक अमला अलर्ट। आईजी और कलेक्टर ने लिया जायजा।

मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासनिक और पुलिस अमला पूरी तरह मुस्तैद है। जबलपुर जोन के आईजी प्रमोद वर्मा ने बरही पहुँचकर हेलीपैड, रोड शो मार्ग, और सभा स्थल की सुरक्षा व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने और

यातायात प्रबंधन के कड़े निर्देश दिए हैं। आज (गुरुवार) कटनी कलेक्टर ने भी कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। उन्होंने मंच व्यवस्था, बैठक व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया ताकि मुख्यमंत्री के पहले आगमन पर कोई कमी न रहे।

भव्य स्वागत और 'बरही चलो' का आह्वान।

मुख्यमंत्री की अगवानी के लिए पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। विधायक संजय पाठक ने क्षेत्रवासियों से भावुक अपील करते हुए कहा है कि यह उत्सव किसानों की जीत का प्रतीक है।

कार्यक्रम के दौरान एक भव्य रोड शो और रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जहाँ जनता पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का अभिनंदन करेगी। 'बरही चलो' के नारों के साथ गांव-गांव में पीले चावल देकर लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है।

बिष्णुप्रिया मणिपुरी समुदाय को जल्द से जल्द केंद्रीय OBC (COBC) देने की मांग

● केंद्रीय OBC न होने के कारण विभिन्न केंद्रीय बलों की परीक्षाओं में उत्तीर्ण कई युवक-युवतियां नौकरी से वंचित।

● मुख्यमंत्री, स्थानीय मंत्री, सांसद और विधायक का ध्यान आकर्षित।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि: असम के विभिन्न जिलों सहित श्रीभूमि जिले के कई क्षेत्रों से जानकारी मिली है कि बिष्णुप्रिया मणिपुरी समुदाय की लंबे समय से सरकार से मांग रही है कि उन्हें केंद्रीय OBC (COBC) का दर्जा दिया जाए। लेकिन अब तक यह मांग पूरी नहीं होने के कारण समुदाय के लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया है कि इस समुदाय के पास केंद्रीय OBC (COBC) का प्रमाणपत्र न होने के कारण कई युवक-युवतियां CRPF सहित विभिन्न केंद्रीय सुरक्षा बलों की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद भी समय पर नौकरी जॉइन नहीं कर पाए। परिणामस्वरूप उन्हें भारत के विभिन्न राज्यों से अपने घर असम लौटना पड़ा।

समुदाय के लोगों ने दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि भारत के त्रिपुरा राज्य में बिष्णुप्रिया मणिपुरी समुदाय को केंद्रीय OBC की सुविधा प्राप्त है, लेकिन असम में इस समुदाय के उम्मीदवारों को यह सुविधा नहीं मिल रही है। ऐसे में असम और त्रिपुरा के बीच इस प्रकार का अंतर क्यों है, इसको लेकर कई जगह सवाल उठ रहे हैं।

इस संबंध में समुदाय की ओर से असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, स्थानीय मंत्री कृष्णेंदु पॉल, सांसद कृपानाथ मल्लाह तथा विधायक बिजॉय मलकर का ध्यान आकर्षित किया गया है। उनसे अनुरोध किया गया है कि इस महत्वपूर्ण विषय को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाकर जल्द से जल्द बिष्णुप्रिया मणिपुरी समुदाय को केंद्रीय OBC का दर्जा दिलाने की व्यवस्था की जाए। समुदाय का कहना है कि यदि शीघ्र निर्णय लिया जाता है, तो जो उम्मीदवार पहले ही विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो चुके हैं, वे नियुक्ति पत्र प्राप्त कर नौकरी में शामिल हो सकेंगे और उनका भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। समुदाय के लोगों ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्तमान सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के नारे को ध्यान में रखते हुए इस लंबे समय से लंबित समस्या का समाधान करेगी और बिष्णुप्रिया मणिपुरी समुदाय के वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के हित में सकारात्मक कदम उठाएगी, इस आशा पर।

विधायक विजय की सक्रियता से मुख्यमंत्री राहत कोष से 285 लोगों को चिकित्सा व शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता (चेक) वितरित

● इस पहल से क्षेत्र के लोगों ने की सराहना।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि: रामकृष्णनगर के लोकप्रिय विधायक विजय मालाकार की सक्रिय पहल पर आज 13 मार्च (शुक्रवार) को उनके निवास पर 285 जरूरतमंद लोगों के बीच चिकित्सा और शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता (चेक) वितरित किए गए। यह सहायता असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के प्रयास से मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) के अंतर्गत प्रदान की गई।

कार्यक्रम के दौरान आर्थिक रूप से असहाय मरीजों और जरूरतमंद परिवारों को वित्तीय सहायता के चेक सौंपे गए। लोगों का कहना है कि इलाज के भारी खर्च से जूझ रहे इन परिवारों के लिए यह सहायता नई आशा की किरण साबित हुई है।

सूत्रों के अनुसार, कई मरीज लंबे समय से गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे और इलाज के खर्च का प्रबंध करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। मामला विधायक के संज्ञान में आते ही उन्होंने तुरंत आवश्यक पहल करते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की। इसके परिणामस्वरूप आज शुक्रवार को औपचारिक रूप से लाभार्थियों के हाथों में सहायता राशि के चेक सौंपे गए। इस पहल को सरकार की जनकल्याणकारी नीति और जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशीलता का प्रतीक माना जा रहा है। सहायता प्राप्त करने वाले मरीजों और उनके परिजनों ने असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा तथा स्थानीय विधायक विजय मालाकार के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर लोकप्रिय विधायक विजय मालाकार ने कहा कि जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए इस तरह की मानवीय पहल आगे भी जारी रहेगी।

दिल्ली मानकपुरा डोरीवालान में विधायक और एस एच ओ अमित ने किया सड़क का उद्घाटन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली, बादल हुसैन मानकपुरा, डोरीवालान, बागरोजी, शादीपुरा, शहरवासियों को बेहतर आवागमन की सुविधा देने के संकल्प के साथ विधायक विषेश रवि ने गुरुवार को गोशाला रोड़,मानक पुरा बाजार वाली गली सड़क शनि मंदीर से डीसीएम चौक तक बनने वाली नयी सड़क के निर्माण कार्य का उद्घाटन नारियल तोड़ कर किया।आम आदमी पार्टी के करोलबाग विधानसभा क्षेत्र से विधायक विषेश रवि ने बताया कि इस महत्वपूर्ण सड़क परियोजना पर करीब 50 लाख से अधिक रुपए की राशि खर्च की जाएगी।सडक निर्माण से पहले यहां पानी निकासी की व्यवस्था की जाएगी, ताकि भविष्य में जलभराव या सड़क टूटने की समस्या न रहे। निर्माण कार्य में केवल उच्च श्रेणी की सामग्री का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। विधायक ने स्पष्ट कहा कि गुणवत्ता में कई समझौतों बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क की हालत काफी समय से खस्ता थी और यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और स्थानीय लोगों का डीमांड भी था कि सकड बने, लेकिन अब सड़क बनने के बाद यातायात सुचारू रूप से चलेगा।इस अवसर पर निगम पार्षद उर्मिला गोतम ने भी क्षेत्र वासियों का आभार व्यक्त किया और लोगों की समस्या भी सुनी और जल्द समस्या हल करने की आश्वासन भी दिए। वहीं शीदीपुरा थाना के एस एच ओ अमीत ने कहा कि सड़क पर ठेली खुंचे व छोटे छोटे दुकानदारों के लिए कार्ड का व्यवस्था किया जाए, ताकि एक गरीब दुकानदारों अच्छा से अपना व्यापार को आगे बढ़ा सके एस एच ओ ने कहा कि यह मार्ग शहर का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है। बेहतर सड़कें न केवल व्यापार को गति देती है, बल्कि दुर्घटनाओं को कम कर समय की भी बचत करती है। सड़क निर्माण कार्य शुरू होने से स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों में खुशी की लहर है। लोगों ने फूल मालाओं के साथ विधायक विषेश रवि का स्वागत किया। इस अवसर पर जन प्रतिनिधि अंकित रवि, क्षेत्र के प्रधान,बंशल जी,रमेश जी,बंटी जी, और पार्टी के कार्यकर्ताओं व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

असम माला 3.0 परियोजना के तहत आनीपुर-दुल्लभछड़ा- चामटिला सड़क का शिलान्यास

● 38 करोड़ से अधिक की लागत से होगा लगभग 10 किमी सड़क का विस्तार, क्षेत्र में खुशी की लहर।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि संवाददाता स्वतंत्र प्रभात: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने आज 13 मार्च (शुक्रवार) बराक घाटी की कई विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। राज्य की सड़क संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई असम माला 3.0 परियोजना के तहत महत्वपूर्ण सड़क विकास कार्यों की शुरुआत हुई। इसी क्रम में श्रीभूमि जिले के रामकृष्णनगर पूर्त टेरिटोरियल रोड डिवीजन के अधीन आनीपुर तिमुखा से दुल्लभछड़ा होकर चामटिला तक लगभग 10 किलोमीटर लंबी सड़क का औपचारिक शिलान्यास विधायक विजय मालाकार की अध्यक्षता में किया गया। समारोह में स्थानीय जनता की भारी उपस्थिति रही, जिससे क्षेत्र में इस विकासात्मक पहल के प्रति उत्साह और समर्थन देखा गया।

जानकारी के अनुसार इस परियोजना को लागू करने के लिए कुल 38 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है। सड़क का आधुनिकीकरण और चौड़ीकरण किया जाएगा। नई सड़क की चौड़ाई 5-6 मीटर तक बढ़ाई जाएगी, और दोनों ओर स्लैब सहित नालियों का निर्माण किया जाएगा, ताकि मानसून में जल निकासी की समस्या दूर हो और सड़क की स्थायित्व बनी रहे।

स्थानीय लोगों के अनुसार यह मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतिदिन कई लोग इसका उपयोग बाजार, शैक्षणिक संस्थानों और कार्यस्थलों तक जाने के लिए करते हैं। सड़क के चौड़ीकरण से क्षेत्र की संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। 'शिलान्यास के अवसर पर क्षेत्रवासियों ने विधायक विजय मालाकार और संबंधित अधिकारियों को धन्यवाद दिया और परियोजना के शीघ्र पूरा होने की कामना की।

निपुण भारत मिशन के तहत दो दिवसीय शिक्षक संकुल क्षमता-वर्धन कार्यशाला का आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सुरियावां, भदोही। आज दिनांक 13 मार्च 2026 को निपुण भारत मिशन के अंतर्गत ब्लॉक संसाधन केंद्र सुरियावां में दो दिवसीय शिक्षक संकुल क्षमता-वर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के प्रथम दिवस में शिक्षक संकुल के उद्देश्य, महत्व, भूमिका एवं उत्तरदायित्व पर विस्तार से चर्चा की गई तथा प्रतिभागियों ने अपने-अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के दौरान संकुल शिक्षकों को आने वाली अकादमिक चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श किया गया और उनके समाधान के लिए विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा की गई। भाषा शिक्षण के संदर्भ में समझ के साथ पढ़ना (Reading with comprehension) तथा उससे संबंधित कक्षा-कक्ष की गतिविधियों पर भी विचार साझा किए गए।

सत्र में यह भी बताया गया कि शिक्षक किस प्रकार बच्चों के लेखन कार्य पर प्रभावी फीडबैक देकर उनके सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं। कक्षा के उदाहरणों के माध्यम से सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बच्चों को मार्गदर्शन देने पर विशेष जोर दिया गया। अंत में रूब्रिक्स कोर्स के संबंध में प्रतिभागियों को जानकारी देते हुए उसकी उपयोगिता पर समझ विकसित की गई और इसी के साथ कार्यशाला के प्रथम दिवस का समापन किया गया। कार्यशाला की सभी गतिविधियाँ समूह कार्य, छोटे एवं बड़े समूह में चर्चा तथा प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से संचालित की

गई। इस अवसर पर LLF के ब्लॉक अकादमिक कॉर्डिनेटर लालचंद यादव, हनुमान जी, एआरपी देवेंद्र कुमार मिश्र, मनोज सिंह, भास्करानंद मिश्र, भैरवानंद यादव, संतोष कुमार सहित शिक्षक संकुल नारायण मिश्र, संतोष शुक्ल, सुनील दुबे, वेद प्रकाश रघुवंशी, भोलानाथ सरोज, मनोज कुमार, अवधनारायण तथा सभी संकुल के शिक्षक उपस्थित रहे।

चंद्रभानु गुप्त कृषि महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा कार्यक्रमो का आयोजन

● युवा ही विकसित भारत के निर्माता हैं: डॉ आरबीएस रावत

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर चंद्रभानु गुप्त कृषि स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का सात दिवसीय विशेष शिविर के तीसरे दिन उत्तराखंड के सेवानिवृत्ति मुख्य वन संरक्षक डॉ आर बी एस रावत ने छात्र-छात्राओं को उनके व्यक्तित्व के विकास और राष्ट्रीय एकता तथा टीमवर्क पर चर्चा की उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना एक ऐसी संस्था है जो युवाओं के सर्वांगीण विकास के साथ राष्ट्र के विकास में मदद कर रही है युवा ही विकसित भारत के निर्माता है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ योगेंद्र कुमार सिंह ने राष्ट्रीय योजना में छात्र में नेतृत्व की भावना का विकास होता है जो राष्ट्र के विकास में बहुत सहयोगी है। मुख्य अतिथि डॉ आर बी एस रावत ने महाविद्यालय कैंपस में वृक्षारोपण भी किया।

ट्रैफिक ट्रेनिंग संस्था के प्रभारी पंकज त्रिपाठी ने छात्र-छात्राओं को ट्रैफिक के नियम बताएं तथा वाद विवाद प्रतियोगिता भी कराई गई। राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य गीत एवं राष्ट्रगान गाकर शिविर का समापन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी धनेंद्र कुमार सिंह, डॉ आशुतोष श्रीवास्तव डॉ दीप्ति श्रीवास्तव, डॉ उपमा त्रिपाठी एवं डॉ सुधीर सिंह रघुवंशी, डॉ हृदय नारायण तिवारी,डॉ स्वाहा सी चंदा, डॉ पी के सिंह, डॉ दीपक पांडे, डॉ अनिल कुमार वर्मा, डॉ विवेक कुमार वर्मा, डॉ अखिलेश शर्मा, डॉ इबाद, डॉ श्वेता मिश्रा, डॉ रश्मि पांडे, डॉ रजनी शुक्ला, डॉ गुरप्रीत भाटिया, डॉ धर्मेश कुमार सिंह, डॉ के डी सिंह, डॉ उरूज आलम सिद्दीकी, डॉ प्रमोद कुमार मिश्रा, डॉ जसकरन सिंह, जितेंद्र कुमार बाजपेई, दिलीप कुमार सिंह, गुलाब यादव, राहुल सिंह, प्रशासनिक अधिकारी शिव मंगल चौरसिया, समन्वयक अधिकारी अजय सिंह भदोरिया, सहित सभी शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित रहे। महाविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉ सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शनिवारको महाविद्यालय कैंपस से एक रैली का आयोजन किया गया है जिसमें जनमानस को जागरूक करने समाज में व्याप्त कुर्तियां को दूर करना तथा समाज को जागरूक करने का काम किया जाएगा। शिविर का समापन कार्यक्रम अधिकारी डॉ आशुतोष श्रीवास्तव ने किया।

बिसवां तहसील के पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा की नई पहल, स्कूल से दूर बच्चों को फिर से जोड़ेगा पहल फाउंडेशन

● पहल फाउंडेशन सक्रिय, ड्रॉपआउट बच्चों का पुनः होगा विद्यालयों में प्रवेश

डॉ. सुधाकर का यह सपना! शिक्षित हो हर बच्चा अपना!

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिसवां (सीतापुर)। पहल फाउंडेशन के तत्वावधान में 'शिक्षा संकल्प' कार्यक्रम के अंतर्गत बिसवां तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत भूरकुड़ी के भुरकुंडी गांव में जागरूकता गतिविधि आयोजित की गई। यह कार्यक्रम प्रख्यात शिक्षाविद् डॉ. सुधाकर वर्मा के प्रेरक स्वप्न 'शिक्षित हो हर बच्चा अपना' को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व, विशेषकर बालिका शिक्षा तथा बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के प्रति जागरूक किया गया। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के समग्र विकास की आधारशिला है। इसलिए प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़कर उनके उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करे। इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीणों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। पहल फाउंडेशन द्वारा संचालित 'शिक्षा संकल्प' अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास माना जा रहा है। पहल फाउंडेशन की संयुक्त सचिव पिंकी प्रजापति ने बताया कि फाउंडेशन द्वारा चयनित गांवों में ड्रॉपआउट और स्कूल से बाहर बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से जन-जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो बच्चे विद्यालय छोड़ चुके हैं, उन्हें पुनः विद्यालय में प्रवेश दिलाने तथा जो बच्चे अभी तक स्कूल नहीं जाते हैं, उनके अभिभावकों से संवाद स्थापित कर उन्हें सरकारी अथवा निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि फाउंडेशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और हर बच्चा पढ़-लिखकर अपने जीवन को बेहतर बना सके। इस मौके पर डॉ. चंद्रशेखर प्रजापति, सतीश वर्मा, प्रेम यादव, पुष्पेंद्र वर्मा, लवकुश यादव, विकास निगम सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

स्वतंत्र प्रभात
जो लिखेगा, वही टिकेगा , वही दिखेगा
स्वतंत्र प्रभात के राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक अखबार, पत्रिका एवं ऑनलाइन चैनल में काम करने हेतु अनुभवी लोगों की आवश्यकता है।
जिला, तहसील एवं ब्लाक स्तर पर ब्यूरोचीफ, संवाददाता और विज्ञापन प्रतिनिधियों की आवश्यकता है। इच्छुक एवं अनुभवी व्यक्ति संपर्क करें।
अपना बायोडाटा भेजे : 9511151254
www.swatantraprabhat.com
www.epaper.swatantraprabhat.com